वर्ष-8, अंक-8, सितम्बर 2020

मूल्य-रुपये 20/-

स्वतंत्र स्वरूप

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

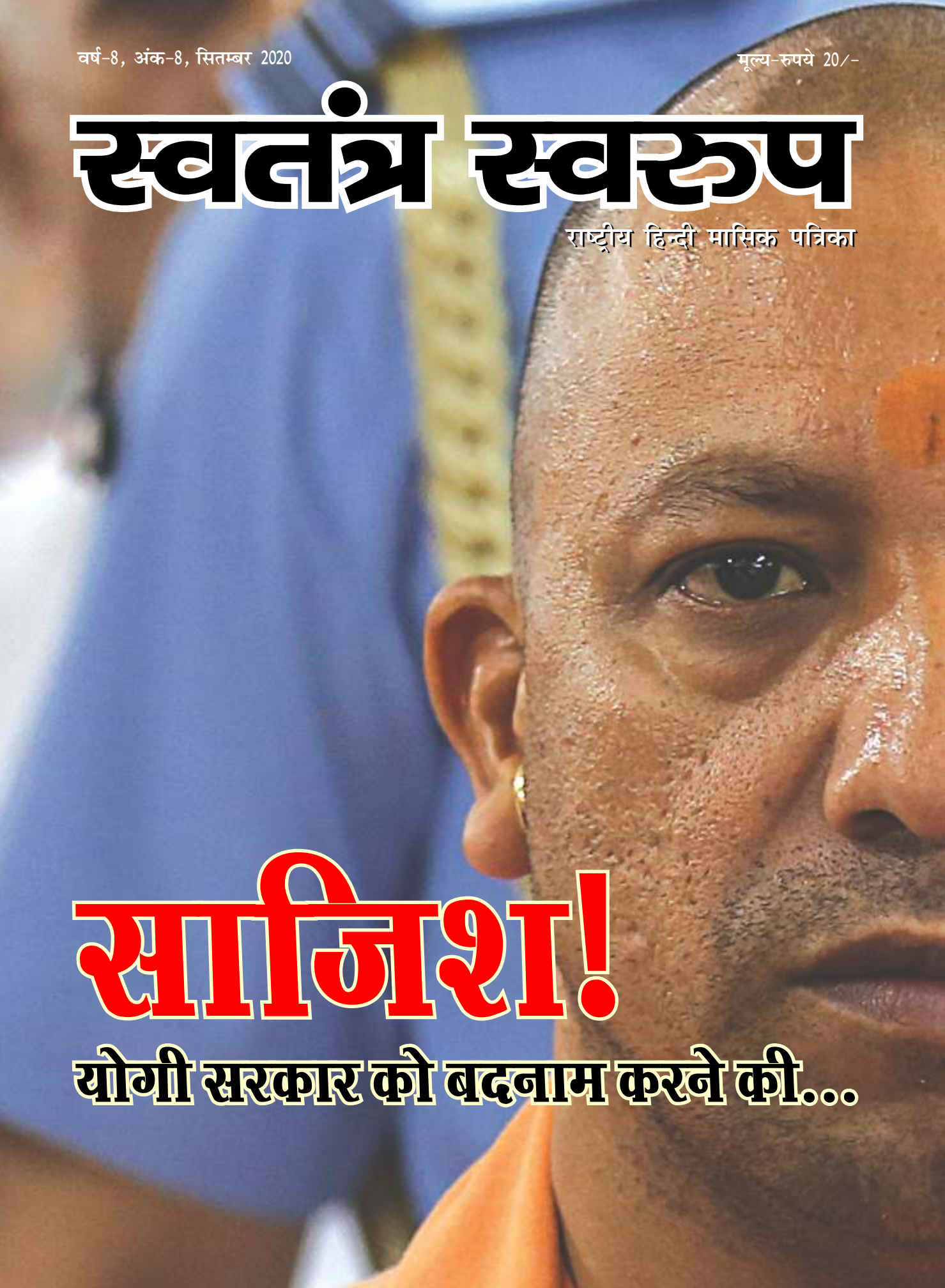

साजिश!

योगी सरकार को बदनाम करने की...

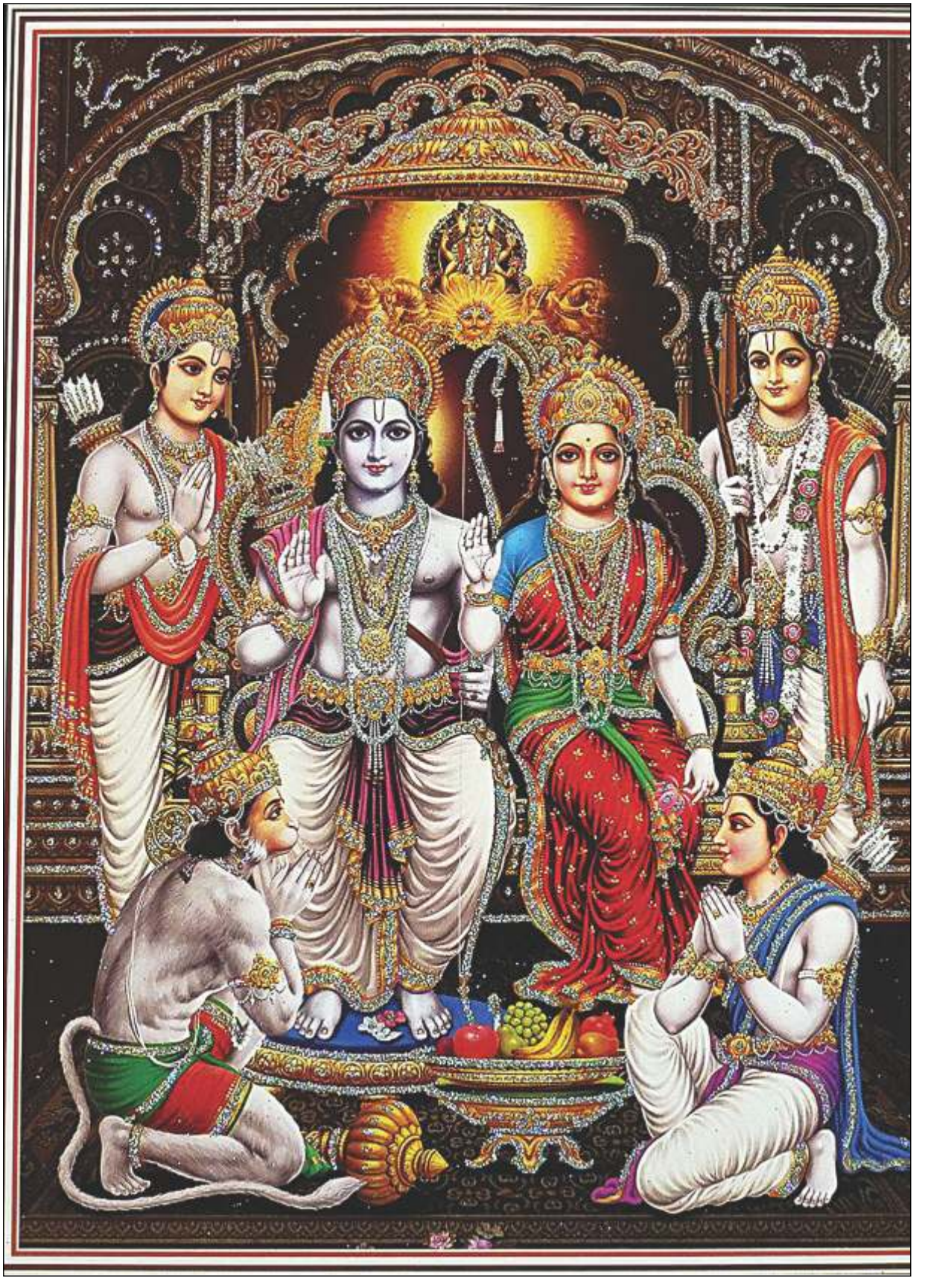

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

स्वतंत्र स्वरूप

वर्ष- 8, अंक- 8, सितम्बर 2020

प्रधान सम्पादक
योगेन्द्र त्रिपाठी

उप-सम्पादक
प्रफुल्ल गोस्वामी

सह-सम्पादक
शशिकांत पाण्डेय
अजय त्रिपाठी

ब्यूरो चीफ (दिल्ली एनसीआर)
हेमेन्द्र त्रिपाठी

विशेष संवाददाता
लखनऊ- दीपक अवस्थी
दिल्ली- श्री निवास सिंह
हरदोई- विभांशु गोस्वामी

विधि-सलाहकार
सतेंन्द्र अवस्थी (एडवोकेट)

जिला प्रतिनिधि
सीतापुर- अनुज शुक्ला
हरदोई- सुरेन्द्र कुमार तिवारी

ले-आउट एण्ड डिजाइन
अजय कुमार

छायाकार
आशीष रमेश
अमित दुबे

कवर फोटो- आशीष रमेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक योगेन्द्र त्रिपाठी द्वारा आफसेट इण्डिया प्रिंटिंग प्रेस मशकगंज लखनऊ से मुद्रित तथा 537भ/307 भरत नगर मोहिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ से प्रकाशित
सम्पादक - **योगेन्द्र त्रिपाठी**

RNI-UPHIN-49702/2013
E- mail:
swatantraswaroop@gmail.com
09454500839, 8840473248

समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

अन्दर के पन्नों पर...

साजिश! योगी सरकार को बदनाम करने की... 06

योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते अधिकारी 12

देश को मिली नई एजुकेशन पॉलिसी 16

एक पहलः पिता के सपनों को पंख लगाकर किसानों को दी नई जिंदगी 18

अस्पताल बना लूट का अड्डा 21

ऑनलाइन एजुकेशनः समस्या और समाधान 23

कोरोना का प्रकोपः शिक्षकों के जीवन से खिलवाड़, विभाग बेखबर 25

डर और अहंकार के कॉकटेल से उपजी एक खास 'प्रजाति' 27

कोविड-19: हर मुसीबत जीवन में कुछ न कुछ सिखा कर जाती है 29

कोरोना की जंग और हारती जिन्दगी 31

जैविक खेतीः- स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 33

कैसे करें आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट 35

हैवानियत की हदें पारः अब करना है मर्दांनगी पर वार 36

इतिहास के नाम पर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ क्यों ? 39

आस्था के साथ खिलवाड़ः शिकायत पर प्रशासन खामोश 42

आवारा पशु हैं इनके दोस्त, मिलिए 'सच्चे इंसान' से 44

कैमरे की नजर में... 45

इतिहास : राम मंदिर का...

योगेन्द्र त्रिपाठी **सम्पादक**

क्या है अयोध्या का इतिहास? क्यों कहा जाता है अयोध्या को राम की जन्म भूमि? कैसे पड़ी राम मंदिर की नींव? कैसे बना था भव्य राम मंदिर? क्यों और कैसे भव्य राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनायी गयी? और लम्बे संघर्ष के बाद अब कैसे एक बार फिर बनने जा रहा है राम लला का भव्य मंदिर? अयोध्या में राम मंदिर की शुरू से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव हुए हैं लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो किस तरह से देश की दिशा और दशा में परिवर्तन होगा।

ऐसे पड़ी नींव

इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्धकाल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। अयोध्या को भगवान श्रीराम के पूर्वज विवस्वान (सूर्य) के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं पर प्रभु श्रीराम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। कहते हैं कि भगवान श्रीराम के जल समाधि लेने के पश्चात् अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ी-सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था।

दोबारा बसी अयोध्या

भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा, महाराजा बृहद्बल तक अपने चरम पर रहा। कौशलराज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने संतों के निर्देश पर यहां भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था।

मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद

14वीं शताब्दी में हिन्दुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंतत: 1527-29 में इस भव्य मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से मस्जिद का निर्माण किया गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्रीराम के जन्मस्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई।

मंदिर के हक में फैसला

6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढ़ांचे को तोड़ दिया गया। जिसके बाद लंबे वक्त तक इस मामले में कोर्ट में मामला चलता रहा। 2010 में कोर्ट ने विवादित जमीन को दोनों पक्षों के बीच बांटने का फैसला सुनाया लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में खारिज करते हुए पूरी जमीन हिन्दुओं की होने का फैसला सुनाया।

टाइम लाइन

1528-29: बाबर के शासनकाल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई।
1853 : हिंदू-मुस्लिम हिंसा की पहली घटना हुई।
1859 : ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने दीवार बना दी गई और दोनों पक्षों को पूजा और इबादत की अनुमति मिली।
1885 : मामला पहली बार अदालत में गया।
1934 : सांप्रदायिक दंगे हुए। मस्जिद के दीवार और गुम्बदों को नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने पुनर्निर्माण कराया।
1949 : भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगवा दिया।
1950 : अदालत से भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी गई
1959-61: दोनों पक्षों ने विवादित स्थल के हक के लिए मुकदमा किया
1984 : विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया।
1986 : ताला खोलने का आदेश दिया।
1989 : विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास किया।
1990 : आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में रोकी गई, गिरफ्तार हुए।
1990 : अयोध्या में पहली बार कारसेवा हुई और गोलीकांड भी।
1992 : बाबरी मस्जिद ढहा दी गई।
1994 : इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस शुरू हुआ।
1997 : मस्जिद ढहाने को लेकर 49 लोग दोषी करार दिए गए।
2001 : विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की।
2002 : सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखें।
2002 : हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू।
2003 : पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की।
2004 : आडवाणी ने अस्थाई मंदिर में पूजा की।
2010 : अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई।
2010 : इलाहाबाद कोर्ट का फैसला- तीन हिस्सों में बांट दिया गया विवादित स्थल।
2011 : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।
2019 : सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया।

मंदिर का नया स्वरूप

राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका और इसके निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस मंदिर के लिए पहले जो मॉडल प्रस्तावित किया गया था अब उसमें संशोधन हो चुका है। पुराने मॉडल की ऊँचाई 128 फीट, चौड़ाई 140 फुट और लंबाई 268/5 फुट प्रस्तावित की गई थी। अब जिस नए मॉडल पर मंदिर बन रहा है उसकी ऊंचाई 161 फुट है, 235 फुट चौड़ाई है और साढ़े 300 फुट लंबाई है। पहले प्रस्तावित मॉडल में 2 की जगह 4 मंडप थे और एक शिखर, अब 4 मंडप और एक शिखर है। इसके साथ ही इस इमारत में 366 खंबे होंगे और सीड़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी।

इतना ही नहीं, मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर प्रांगण में पौराणिक पात्रों सीता, लक्ष्मण, गणेश और हनुमान के लिए अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे। इस मंदिर के निर्माण में 6 लाख क्युबिक फीट पत्थर लगेगा। ये पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया है। इस मंदिर में नीचे गर्भगृह होगा और ऊपर राम दरबार। यह मंदिर दिखने में तीन मंजिला दिखेगा लेकिन तीसरी मंजिल पर कोई छत नहीं पड़ेगी असल में यह दो मंजिला ही होगा। इस मंदिर में राम राज्य की संकल्पना दिखेगी। इस मंदिर में एक साथ 50 हजार लोग दर्शन कर सकेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये मंदिर अगले तीन से चार सालों में बनकर तैयार हो जाएगा।

कितना और कैसे बढ़ेगा पर्यटन

अयोध्या में मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी। 2019 में यहां कुल 3.4 लाख टूरिस्ट यहां आए थे। वहीं, 2015 में 1.4 लाख यानी पिछले पांच साल में 2.5 गुना पर्यटक बढ़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर बनने के बाद यहां करीब 1 लाख तक लोग हर दिन दर्शन के लिए आएंगे यानी करीब 3.6 करोड़ हर साल। देश में डोमेस्टिक टूरिज्म के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर है, जबकि विदेशी पर्यटकों के मामले में तीसरे नंबर। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या ग्लोबल टूरिज्म सेंटर बनेगा।

क्या मिलेगा अयोध्या को

1. **भव्य राम मूर्ति:** यहां भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का भी प्लान है, जिसको लेकर काम चल रहा है। यह मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति होगी, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी।

2. **बनेगा श्रीराम एयरपोर्ट:** अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट बनाया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2018 में इसकी घोषणा की थी। इसके लिए यूपी सरकार ने 200 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। कुल 500 करोड़ रुपए का बजट है। अयोध्या में हाईटेक एयरपोर्ट बनने के बाद यहां आने वाले टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

3. **हाईटेक रेलवे स्टेशन:** अयोध्या में हाईटेक रेलवे स्टेशन भी बनेगा। उम्मीद है कि अगले साल तक काम पूरा हो जाएगा। इस रेलवे स्टेशन को अयोध्या के मंदिर मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए 104 करोड़ रुपये बजट रखा गया है।

साजिश!

योगी सरकार को बदनाम करने की...

योगी सरकार को खोखला कर रहे सिस्टम के दीमक

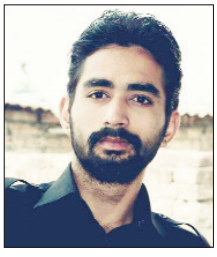

हेमेन्द्र त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्दीधरियों द्वारा रचे गए षड़यंत्र का शिकार हुए राजधानी लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र निवासी मनीष मिश्रा का पूरा परिवार पूर्ण रूप से तबाह होने की कगार पर आ चुका है। शासन से जुड़े आला अधिकारियों ने पीड़ित को न्याय दिलाने में भरपूर सहयोग किया। मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर श्री सुजीत पांडे द्वारा किए गए सहयोग के बाद पीड़ित मनीष में बची जिंदगी को अपने बच्चों के साथ जीने की आस जगी। पूरी घटना पर की गई छानबीन से मिली जानकारी के बाद पीड़ित मनीष को न्याय दिलाने के लिए स्वतंत्र स्वरूप के एनसीआर ब्यूरो चीफ **हेमेन्द्र त्रिपाठी** की खास रिपोर्ट -

सूबे में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को भय मुक्त, अपराध मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो वादा किया था, उसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के लिए दिन-रात एक कर अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का पूरा प्रयत्न किया। परन्तु, वर्तमान सरकार में कुछ पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्ट एवं चाटुकार अधिकारी पूरे प्रशासनिक ढांचे को दीमक की तरह खोखला करके सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में जब भी कानून व्यवस्था की बात की जाती थी तो लोगों की जुबां पर सिर्फ मायावती की सरकार का नाम सबसे पहले आता था लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता के मनोमस्तिष्क में बसपा सरकार द्वारा छोड़ी गई छाप धूमिल होती नजर आने लगी, जिसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया। ऐसा हो भी क्यों न? आखिरकार, पूर्व की सरकार और उनके अधिकारियों व उन्हीं सरकारों की शरण में पल रहे माफियाओं द्वारा किए गए अपराधों और भ्रष्टाचारों का खात्मा करने की जिम्मेदारी के चलते एक बड़ी जीत के साथ सरकार जो बनाई थी। लेकिन कहा जाता है कि किसी सरकार की छवि को नकारात्मक से सकारात्मक और सकारात्मक से नकारात्मक

लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डे के आश्वासन से पीड़ित मनीष को जगी न्याय की आस।

तक का सफर तय करने में अधिक समय नहीं लगता क्योंकि उस सफर में सरकार से अधिक समर्पण उनके आला अधिकारियों का होता है। सख्त प्रशासनिक क्षमता के लिए जानी जाने वाली योगी सरकार में बैठे कुछ पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्ट अधिकारियों के चलते एक ओर जहां सरकार की छवि दागदार होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के गरीब व वर्दी के रौब से अनजान रहने वाले एक आम नागरिक को विभाग के ही पुलिसकर्मी उसे गैंगस्टर जैसा संगीन अपराधी बनाने के साथ

तत्कालीन डीसीपी उत्तरी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जिनकी अहम भूमिका से फर्जी केस के खुलासे की हुई शुरूआत।

उसकी सामाजिक छवि को दागदार बना कर उसे आत्महत्या करने पर विवश कर देते हैं। जिसका एक जीता-जागता उदाहरण सूबे की राजधानी कहे जाने वाले लखनऊ में देखने को मिला, जहां राजधानी की तत्कालीन अलीगंज पुलिस का शर्मनाक चेहरा मानवता को लगातार शर्मसार करता चला आ रहा है।

घटना राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले त्रिवेणी नगर की है। जहां अहिबरनपुर पॉवर हाउस के निकट रहने वाले पूर्व आईजी(सीआईडी) प्यारेचंद्र के पुत्रों व स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के चलते एक हँसते-खेलते खुशहाल परिवार का जीवन बर्बाद हो गया। घटना में पीड़ित मनीष मिश्रा की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देख कर यकीनन हर पत्थर दिल इंसान रोने के लिए विवश हो जाएगा। मनीष ने अपनी जिंदगी में बीतें उन पन्नों को फिर से पलट कर पढ़ने का प्रयास किया, जिसे एक बार पढ़ना भी किसी बड़े साहस से कम नहीं है। स्वतंत्र स्वरूप की टीम जब पीड़ित मनीष मिश्रा से बात करने पहुंची तो मनीष ने रोते हुए बताया कि किस प्रकार चंद दिनों में उनके परिवार के साथ उनका सब कुछ खत्म कर दिया गया। पुलिस द्वारा किए जा रहे आर्थिक, शारीरिक व मानसिक अत्याचार के साथ जीवन यापन के लिए रोजी-रोटी का सहारा बनी दुकान को लूट कर स्थानीय थाने की पुलिस बिना किसी अपराध के उसी दुकान के सामने से पीड़ित को थाने ले जा कर छोड़ने के बदले में भारी रकम की मांग करती है। इतना ही नहीं, पीड़ित से की गई मांग पूरी न होने पर पुलिस द्वारा पीड़ित मनीष को लगभग 3 दिन थाने में रखकर भीषण प्रताड़ना के साथ कई संगीन मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है। घटना यहीं खत्म नहीं होती, इसी प्रकरण के दौरान जब पीड़ित की पत्नी बिना किसी अपराध के जेल में बंद अपने पति से मिलने जाती है तो पीड़ित के कथनानुसार पत्नी की किसी षड़यंत्र के चलते ही हत्या करा दी जाती है, जिसे स्थानीय पुलिस दुर्घटना का रूप देकर मामले से किनारा करने से भी नहीं चूकती।

पीड़ित मनीष मिश्रा ने अपने जीवन में घट रही घटना के उस शुरुआती भाग का जिक्र किया जिसे सुनकर आज के दौर में जीने वाले हर सामाजिक व्यक्ति का वर्दीधारियों द्वारा किए जाने वाले न्याय से विश्वास उठ जाएगा। मनीष ने पूर्व आईजी के पुत्रों और बहुओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते वर्ष 2012 में पूर्व आईजी प्यारेचंद्र के पुत्र संतोष सिंह से 12000 रुपये प्रति माह पर एक दुकान किराये पर लेकर 'सिटी कैफे रेस्टोरेंट' के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद आरोपी संतोष ने रेस्टोरेंट को अपनी उचाईयों पर पहुंचते देखकर ईर्ष्या के कारण दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। रोजी-रोटी जाने के डर से परेशान मनीष समस्या से निकलने का कोई मार्ग खोज ही रहा था कि आरोपी संतोष सिंह ने मजबूरी का लाभ उठाते हुए एक ऐसा कुचक्र रचा, जिसमें दुनिया के छल-प्रपंच से दूर रहने वाला गाँव का सीधा-साधा व्यक्ति फसता चला गया। पीड़ित मनीष ने बताया कि संतोष ने मुरादाबाद में चल रहे अपने होटल को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता का हवाला देकर दुकान को किराए पर लेने की जगह 40 लाख में बेचने का प्रस्ताव रख दिया। जवाब के तौर पर मनीष के द्वारा इतने पैसे न होने व दुकान न खरीद पाने की स्थिति को बताने पर आरोपी संतोष ने 5 लाख की तत्काल व्यवस्था करने को कहा, साथ ही दुकान की कीमत 40 लाख की जगह 30 लाख कर दी। समय की मार से जूझ रहे पीड़ित मनीष ने किसी तरह अपनी पत्नी के जेवर आदि बेच कर तथा संबंधियों से पैसे उधार लेकर 5 लाख रुपए पूर्व आईजी के पुत्र संतोष सिंह को दे दिए और बकाया राशि को जल्द ही देने की बात कही। एक साधारण से व्यक्ति द्वारा शुरुआत में ही इतनी भारी रकम देने के कुछ दिनों बाद ही संतोष ने पीड़ित मनीष को किसी नए षड़यंत्र का मोहरा बना कर कहा कि 'तुम्हे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा काम चल गया है। तुम मेरी छोटी-मोटी जरूरत पड़ने पर 40-50 हजार रुपए यदि हर महीने समय से दे दिया करोगे तो जल्दी ही बकाया राशि भी पूरी हो जाएगी और जब बाद में व्यवस्था और उचित समय हो तो दुकान की रजिस्ट्री करा लेना। तब तक जो पैसा तुम दे चुके

साजिश का शिकार होने से कुछ दिन पूर्व पीड़ित मनीष का खुशहाल परिवार

हो और जो देने वाले हो, उसका हिसाब रखने के लिए एक डायरी बना लो। जितना पैसा तुम मुझे दोगे, उसे हम तुम्हारी डायरी में लिख कर हस्ताक्षर कर दिया करेंगे और वह डायरी तुम अपनी दुकान के काउंटर में रखना'। आने वाली समस्याओं के लिए बनने वाली योजनाओं में फसते जा रहे मनीष को संतोष सिंह का यह सुझाव उचित लगा, जिसके बाद वह हर माह संतोष को उनकी आवश्यकता के अनुसार मांगी गई राशि देने लगा। इसी बीच संतोष को अधिक आवश्यकता पड़ने पर 1 लाख रुपये भी दिए। समय मिलता गया और पीड़ित अपने खर्चे को सीमित कर बचत किए गए पैसे संतोष को देता गया। संतोष को दी जाने वाली राशि में कमी होते देख पीड़ित मनीष ने अपने रेस्टोरेंट के पड़ोस में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक से सम्पर्क कर दुकान के नाम पर सीसी लिमिट बनवाने हेतु निवेदन किया, जिसपर शाखा प्रबंधक ने मौजूदा समय के कुछ दिन के बाद सीसी लिमिट बनाने के लिए सहमति प्रदान कर दी। समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, पीड़ित मनीष मेहनत से कमाई गयी अपनी थोड़ी-थोड़ी जमापूंजी को इकट्ठा कर आरोपी संतोष, उसकी पत्नी व उसके भाई अरविंद को देता गया। धीरे-धीरे 15 लाख तक की धानराशि संतोष तक पहुंच चुकी थी। अपने कहे अनुसार 2017 में बैंक के शाखा प्रबंधक ने 7 लाख रुपये की सीसी लिमिट बना दी। उक्त लिमिट का रुपया कई किश्तों में पीड़ित के बैंक खातों में आता गया और मनीष के माध्यम से वह सम्पूर्ण धनराशि आरोपी संतोष तक पहुंचती चली गयी।

उसी दौरान पीड़ित मनीष ने आरोपी संतोष से दुकान की रजिस्ट्री करने के लिए समय निकालने को कहा तो संतोष सिंह ने समय मिलते ही जल्द से जल्द बैनामा करने की बात कही। थोड़ा समय बीतने के बाद संतोष सिंह ने अक्टूबर 2017 में पीड़ित मनीष से कहा कि 'अपना पैसा और गवाह लेकर कचहरी पहुँचो, हम बैनामा करने आ रहे हैं।' पीड़ित अपनी पत्नी व अन्य लोगों के साथ कचहरी पहुंच कर बैठ गया, मौके पर आरोपी संतोष का फोन ऑफ जाने पर वह देर शाम तक कचहरी में ही उसका इंतजार करता रहा। शाम को पीड़ित के वापस आने पर पता चला कि आरोपी संतोष मुरादाबाद चला गया है। अधिक समय बीता भी नहीं था कि एक दिन संतोष की पत्नी और संतोष के भाई की पत्नी के बीच आपसी कहासुनी के चलते यह बात सामने आई कि जिस दुकान के लिए लाखों रुपए पीड़ित मनीष से आरोपी संतोष द्वारा लिए गए हैं, वह दुकान संतोष की न होकर किसी अन्य की है। इतनी बड़ी बात के पता लगते ही मानो मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बस इसी क्षण के पीड़ित मनीष की बर्बादी के समय की शुरुआत हो जाती है।

कुछ दिन बाद संतोष के मुरादाबाद से वापस आने की सूचना पाकर पीड़ित मनीष ने संतोष से बैनामा करने अथवा पैसे वापस करने की मांग की तो संतोष ने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर कई धमकियां देना शुरू कर दिया। मामला गंभीर होता देख पीड़ित मनीष ने तत्काल ही एक लिखित सूचना के रूप में घटना की जानकारी अलीगंज थाने के अंतर्गत आने वाली स्थानीय चौकी गल्लामंडी के चौकी प्रभारी को देकर मदद की गुहार लगाई। लिखित सूचना देने के बाद कुछ समय बीता ही था कि एक दिन गल्लामंडी के चौकी प्रभारी अपने दो सिपाहियों व आरोपी संतोष के साथ आकर रेस्टोरेंट में बैठ कर कुछ खाने का ऑर्डर दिया। खाना उनके सामने रखी मेज पर सर्व करने के तुरन्त बाद ही आरोपी संतोष ने खाना खराब होने का झूठा आरोप लगाते हुए पीड़ित को अपशब्द कहने के साथ-साथ गर्म खाने को मनीष के ऊपर फेक दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो आरोपी संतोष ने पीड़ित की लात-घूसों से पिटाई करते हुए वर्दीधारियों के सामने जान से मारने की धमकी दी।

दिहाड़ी मजदूर दिव्यांग राजू उर्फ इरफान जिसे पुलिस व पूर्व आईजी के पुत्रों की साजिश ने बनाया गैंगस्टर का अपराधी।

वर्दीधारियों के सामने ऐसी दबंगई देख कर पीड़ित बुरी तरह घबरा गया था। पीड़ित मनीष ने इस प्रकरण में आगे घटित हुई घटना के विषय में बताते हुए कहा कि रेस्टोरेंट में पुलिस वालों के सामने घटित हुई घटना के कुछ दिन बाद ही दिनांक 15 जुलाई 2018 को प्रातः लगभग 6:30 से 7:00 बजे रोजाना की तरह पीड़ित अपने दिव्यांग नौकर राजू के साथ मंडी से सब्जी लेकर अपनी दुकान का आधा शटर खोला ही था कि चौकी के 4 सिपाही आकर पीड़ित को दरोगा के द्वारा बुलाए जाने का आदेश सुना देते हैं। पीड़ित के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर एक-एक करके पीड़ित व उसके नौकर राजू को बैठा लिया। पीड़ित ने जब अपने दुकान का शटर बंद करने को कहा तो सिपाहियों ने कुछ देर बाद अभी वापस आने की बात कह कर पीड़ित व उसके नौकर राजू को चौकी ले आए, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित पर अपना रौद्र रूप दिखाते हुए बेतहाशा थप्पड़ व डंडों के साथ तरह-तरह से प्रताड़ना के तरीके अपनाना शुरू कर दिया। पीड़ित द्वारा जब इतनी भीषण प्रताड़ना का कारण पूछा गया तो आरोपी संतोष की शिकायत करने का खामयाजा भुगतने व 5 लाख रुपये की मांग की। इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था न कर पाने के चलते परेशानी से जूझ रहे पीड़ित मनीष को 3 दिन चौकी से थाने तक रोज की भांति प्रताड़ित किया जाने लगा। इतनी प्रताड़ना होने के बाद भी जब न्याय के पुजारी कहे जाने वाले वर्दीधारियों की 5 लाख वाली मांग जब पूरी नहीं हुई तो दिनांक 17 जुलाई 2018 को एक एटीएम लूट की योजना बना कर व फर्जी षड़यंत्र रच कर अलग-अलग कई मुकदमें

कर पीड़ित को जेल भेज दिया गया। जेल जाने के दूसरे दिन जब पीड़ित की पत्नी झूठे आरोपों में फंसे अपने पति से मिलने आ रही थी तो प्रात: 7:00 बजे के आस-पास पारापुल के पास पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें पीड़ित को संदेह है कि पत्नी के साथ अचानक हुई घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि यह आरोपी संतोष द्वारा रची गई साजिश का एक हिस्सा है, जिसमें मेरी पत्नी की जानबूझ कर हत्या कराई गयी है।

लगभग 2 माह बाद जेल से छूट कर आने पर किसी तरह पीड़ित ने अपने दो छोटे-छोटे बच्चों को पालना शुरू कर दिया। एक दिन पीड़ित मनीष अपने बच्चों के टूटे हुए चप्पलों के सिल. वाने पड़ोस की एक दुकान पर गया था। पीड़ित दुकान पर खड़े होकर बच्चों के चप्पल सिलवा ही रहा था कि अचानक कहीं से 3 से 4 सादी वर्दी में पुलिस ने आकर बच्ची को दूर करते हुए पीड़ित मनीष को गाड़ी पर बैठा लिया और क्षेत्रीय मड़ियांव थाने ले आए। देर रात तक मड़ियांव थाने में रोके रखा, जिसके बाद अलीगंज थाने ले जा कर पीड़ित मनीष मिश्रा का गैंगस्टर में चालान कर दिया गया।

पुलिस द्वारा जिस व्यक्ति पर गैंगस्टर जैसे संगीन मुकदमें को दर्ज किया गया था वह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कृत्य था। जेल से फिर लगभग 3 से 4 महीने बाद छूटने पर पीड़ित तो मानो सरकार में बैठे कुछ जयचंदों के कारण अपना सब कुछ गवा कर दर-दर की ठोकरें खाता हुआ कुछ समाजसेवियों की शरण में गया। पीड़ित मनीष की व्यथा सुनकर नेकदिल इंसानों ने अपने तरीके से कुछ पत्रकारों को साथ लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की आस में मिलने का प्रयास किया, जहां मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी ने मिल कर पीड़ित के साथ घटित हुई पूरी घटना को समझते हुए उच्च अधिकारियों को जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ समय बाद पीड़ित मनीष ने अपना सहयोग करने वाले समाजसेवी व पत्रकार साथियों के साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे से मिलकर उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई और न्याय की मांग रखी।

यही वह समय था, जहां से पीड़ित के मन में न्याय की आस जगी। शासन के आदेशानुसार जांच एजेंसियां अपनी निष्पक्ष जांच में जुट गईं। परन्तु, ऊंची पहुंच और अपने रुतबे के आगे कुछ जांच एजेंसियां अपने को असहाय महसूस करने लगीं क्योंकि एक ओर पूर्व आईजी के पुत्रों का रुतबा, प्रशासन में पकड़, वर्दी का जलवा व न्यायिक विभाग में कुछ रिश्तेदार थे, वहीं दूसरी ओर उनकी ही मदद में लगे रहकर स्थानीय पुलिस के कुछ वर्दीधारी व सत्ता के चाटुकार जयचंद थे। जिनके हाथों में वर्दी की वह ताकत थी, जिससे वह किसी को भी जेल भेज सकते थे। जिसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में महीनों-सालों के वक्त गुजरने पर वह पीड़ित अपनी जिंदगी का काफी समय मुकदमा-पेशी के झंझटों में गुजार देगा, जैसा कि इस घटना में पीड़ित मनीष मिश्रा के साथ घटा। आरोपी संतोष ने अपने पिता के रसूख का सहारा लेकर मजाक-मजाक में हँसते-खेलते परिवार को एक तिनके की भांति ऐसे उजाड़ा कि अगली बार वह अपनी जिंदगी जीने के लिए भी सौ बार सोचने पर मजबूर होगा।

पीड़ित मनीष अपने बच्चों के साथ तिल-तिलकर जिन्दगी जीने को मजबूर।

पीड़ित मनीष मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा पीड़ित व उसके परिवार पर मनगढ़ंत कहानी रचने से पहले कभी भी कानून की छोटी से छोटी धारा 107/16 की धारा भी थाने में दर्ज नहीं है, कभी किसी से विवाद नहीं हुआ फिर आखिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी गयी। मेरा कारोबार, मेरी दुकान भी अच्छी तरह चल रही थी। परिवार वालों के साथ चौकी के लगभग सभी लोगों के लिए खाने आदि की व्यवस्था भी करता था। संतोष और उनके परिवार के लोग अक्सर खाना हमारे रेस्टोरेंट से ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, परिवार में आने-जाने वाले लोगों को भी नाश्ता पानी आदि हमारे यहां रेस्टोरेंट में ही कराते थे। पीड़ित मनीष ने यह भी कहा कि हमारे रेस्टोरेंट के प्रयोग में आने वाली सब्जी आदि वे बड़ी ही सरलता से अपने घर ले जाया करते थे, इतना सब करने के बाद भी मानवता को शर्मसार कर देने वाली इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दी गयी। उक्त घटना को देखते हुए कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अचानक ऐसी घटना घटित होना घटना को संदिग्ध बताता है। पीड़ित मनीष का आरोप है कि मेरा लाखों रुपए जो आरा. पी संतोष ने अपनी दुकान बेचने के लिए मुझसे विश्वास बना कर लिया था, उसने मुझे झूठे आरोपों में फंसा कर व जेल भेजकर अदा कर दिया, जिसके चलते मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि एटीएम लूट व

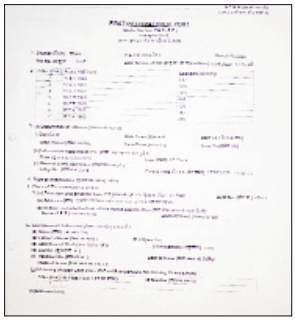

पूर्व आईजी के पुत्रों के खिलाफ दो वर्ष बाद दर्ज एफआईआर की प्रति।

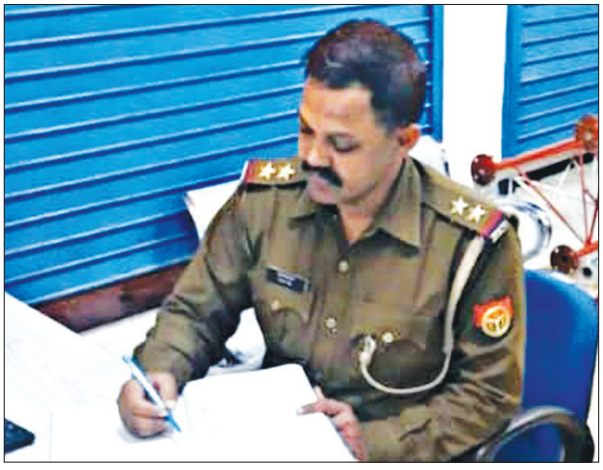

तत्कालीन चौकी इन्चार्ज गल्ला मण्डी थाना अलीगंज जिनकी कथित साजिश का शिकार गरीब दिहाड़ी मजदूर व अन्य

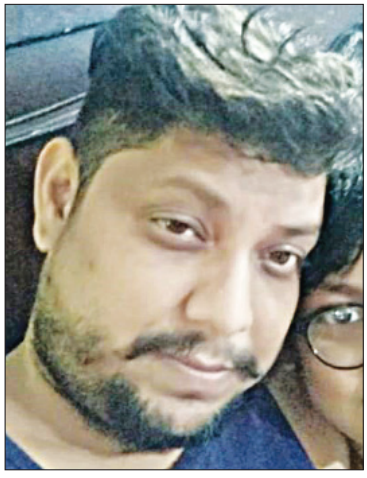

पूर्व आईजी के पुत्र संतोष सिंह जिनकी कथित साजिश का शिकार हुआ पीड़ित मनीष व दिव्यांग राजू

सीतापुर रोड जैसे व्यस्त इलाके में गोली चलने की किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी और ना ही किसी के द्वारा सुनी गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि मनीष को स्थानीय पुलिस चौकी गल्ला मंडी के कुछ सिपाही प्रातः लगभग 7/00 बजे दुकान खोलते वक्त 15 जुलाई 2018 को मोटरसाइकिल पर ले गए थे। कुछ देर बाद वही पुलिसकर्मी (नाम ज्ञात नहीं) वापस आकर दुकान के बाहर खड़ी पीड़ित मनीष की मोटरसाइकिल उठा ले गए। यदि मनीष की बात का समर्थन करने वाले शपथपत्र और प्रत्यक्षदर्शियों की बात को सही माना जाए तो तत्कालीन थाने के वर्दीधारी व उसी थाने से संबंधित गल्लामंडी चौकी के वर्दीधारी संदेह के घेरे में साफ-साफ नजर आते हैं। इतना ही नहीं, स्वतंत्र स्वरूप की टीम ने जब पीड़ित मनीष के रेस्टोरेंट में काम करने वाले त्रिवेणीनगर निवासी राजेश, भरत नगर निवासी रोहित, सीतापुर निवासी राकेश सिंह से पीड़ित के साथ घटित हुई घटना की जानकारी मांगी तो उन्होंने आरा. पी संतोष पर रुतबा दिखा कर व दबाव डाल कर पैसा वसूलने जैसे कई आरोप लगाते हुए मनीष के साथ हुई घटना को सही बताया, साथ ही उन्हें जल्द ही न्याय दिलाने की मांग की।

षड़यंत्रकारियों द्वारा रचे गए षड़यंत्र की कहानी कुछ ऐसी है कि एटीएम में पहले से कोई संदिग्ध कुर्ता पहना कर भेजा जाता है, फिर वही कुर्ता पीड़ित मनीष को जबरदस्ती थाने में पहनाया जाता है। उसकी जिंदगी को तबाह करने के लिए 3 दिन थाने में रखकर 17 जुलाई को चालान कर दिया जाता है, फिर दुर्घटना का रूप देकर पत्नी की हत्या करा दी जाती है। जेल मिलने जाने पर घटना के दूसरे ही दिन हत्या की घटना का घटित होना संदेहास्पद बनाता है।

घटना के संदर्भ में एक स्थानीय थाने के वर्दीधारी पुलिस से बात करने पर उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि कोई अधिकारी इस घटना का खुलासा कुछ जानने के बावजूद भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लगभग 15 से 20 स्थानीय थाने के पुलिस वाले फसेंगे। इतना ही नहीं, मामला इतना बड़ा और संगीन है कि अगर उसका सही तरह से खुलासा हो गया तो पुलिस वालों का परिवार भी तबाह होने की कगार पर आ जाएगा, जिसके चलते अभी तक इस घटना का कोई खुलासा नहीं हुआ है और आगे भी इस घटना का खुलासा होना संभव प्रतीत नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस घटना की निष्पक्ष जांच सीबीआई अथवा मजिस्ट्रेट से कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है।

घटना से संबंधित तत्कालीन पुलिसकर्मियों व संतोष सिंह से जब इस मामले पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने उक्त घटना पर बात करने से इनकार करते हुए घटना को नया मोड़ देने का प्रयास भी किया।

लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे व तत्कालीन डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी की न्यायप्रिय शैली के चलते की गई जांच के बाद घटना के मुख्य आरोपी व पूर्व आईजी के पुत्रों संतोष आदि के खिलाफ थाना अलीगंज में अपराध संख्या 187/2020 आईपीसी की धारा 147, 504, 506, 406, 420, 457, 380 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित मनीष के जेल जाने के बाद उसकी दुकान का ताला तोड़ कर लुटे गए लाखों रुपये, जरूरत का सामान जैसे एसी, फ्रिज, फर्नीचर आदि को चोरी कर के बेच दिया गया था, जिसे वहां की स्थानीय पुलिस के अथक प्रयासों से लगभग बरामद किया जा चुका है और अभी काफी सामान बरामद होना बाकी बताया जा रहा है। चूंकि, मामला पूर्व आईजी के परिवार से जुड़ा है इस कारण से स्थानीय पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने से बच रही है।

तत्कालीन चौकी इन्चार्ज राहुल तिवारी, रामलीला मैदान थाना मंडियांव जिन्होंने पीड़ित मनीष को कथित हिस्टीशीटर बनाने की रची थी साजिश।

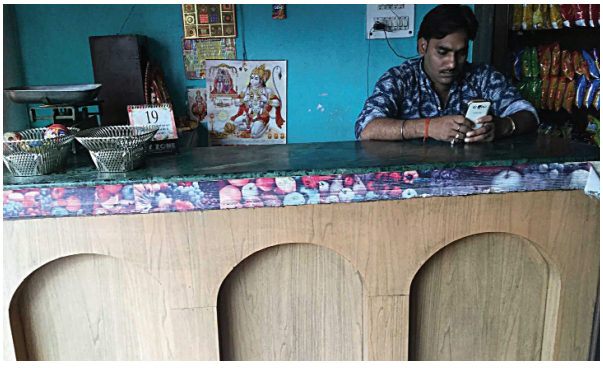

एक तरफ पूर्व में घटित हुई इतनी गंभीर घटना को सामान्य होता व स्वयं को न्याय मिलता देख पीड़ित मनीष मिश्रा राहत की सांस लेने का प्रयास कर ही रहा था कि दूसरी ओर थाना अलीगंज क्षेत्र स्थित गल्लामंडी पुलिस चौकी के तत्कालीन चौकी इंचार्ज ने अपने को फसता देख मनीष मिश्रा के मड़ियांव थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्र रामलीला के चौकी इंचार्ज राहुल तिवारी द्वारा दबाव बनवा कर फर्जी मुकदमें में फिर से जेल भेजने की धमकी दी। इस प्रयास में भी सफल न होने पर उसी क्षेत्र की एक महिला (जो कि मनीष के घर की पूर्व किराएदार थी) से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर, लालच आदि देकर मनीष के खिलाफ नया मामला तैयार करके खड़ा कर दिया। महिला के मुताबिक पुलिस ने यह कह कर दबाव बनाया कि 'मनीष के खिलाफ बोलने पर तुम्हे भी फायदा होगा और मुझे भी। तुम्हे सिर्फ मनीष के खिलाफ एक प्रार्थनापत्र लिखकर उच्चाधिकारियों को पहुंचाना होगा'। महिला ने जब पुलिस द्वारा बनाए जा रहे दबाव का विरोध किया तो उसे समाज के समक्ष बदनाम करने और झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी भी दी गयी। इस प्रकरण में मड़ियांव थाना क्षेत्र स्थित रामलीला के तत्कालीन चौकी इंचार्ज राहुल तिवारी के साथ एक अज्ञात वकील व डीसीपी कार्यालय में तैनात नैपाल सिंह के साथ उनके एक कथित रिश्तेदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने पीड़ित मनीष मिश्रा के खिलाफ उच्चाधिकारियों से गोपनीय आदेश कराकर गोपनीय रूप से पीड़ित को बिना किसी जानकारी के अपराध संख्या 409/2020 के अंतर्गत धारा 493, 406, 504, 506 में थाना मड़ियांव में ही मुकदमा दर्ज करा कर तत्काल बिना देरी के विवेचना पूरी करके हिस्ट्रीशीटर बनाने का कुचक्र रच दिया। मामला यहीं खत्म नहीं होता, पुलिसकर्मियों ने पीड़ित मनीष को किसी तरह जेल भेजने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। परन्तु, 'भगवान के घर देर है अंधेर नहीं' की कहावत सच साबित हुई, पीड़ित मनीष मिश्रा की गिरफ्तारी के कुछ क्षण पूर्व किसी से सूचना पाकर पीड़ित शिकायत करने वाली महिला के साथ डीसीपी उत्तरी शालिनी सिंह से मिलकर उन्हें पुलिसवालों द्वारा बनाए गए दबाव और अपने साथ घटित हुई घटना से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित की बात सुनकर डीसीपी शालिनी सिंह ने पीड़ित मनीष पर दर्ज हुए फर्जी मुकदमें की निष्पक्ष जांच करने के लिए मड़ियांव के थाना प्रभारी को आदेशित किया, साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच में यदि पीड़ित पर लगाया गया मुकदमा फर्जी साबित होता है तो मुकदमा रद्द करने के साथ-साथ इस पूरे प्रकरण में आरोपी साबित हुए पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी से पता चलता है कि पीड़ित मनीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज कथित फर्जी मुकदमे की जांच की प्रक्रिया के चलते सालों से एक ही चौकी पर जमे रहने वाले रसूखदार दरोगा नैपाल सिंह को पहले स्थानांतरित किया गया था। परंतु, उसके बावजूद भी वे जांच को प्रभावित करते रहे, जिसके चलते पुनः उनका स्थानांतरण कर दिया गया। विभागीय परिवार के चलते मनीष के क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज का साथ लेकर नैपाल सिंह द्वारा अपने को बचाने के लिए एक ऐसा ताना-बाना बुना गया कि एक परिवार जो पहले से ही मृत समान था, उसे पुनः जेल भिजवा कर महीनों व सालों तक जेल में ही जिंदगी गुजारनी पड़े और वे इस मामले से जुड़ी जांच से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अपनी वर्दी के रुतबे की ताकत से इतनी बड़ी सजा जिससे शायद ही वह निरपराधी व्यक्ति जीवित बच पाता। कुछ विभागीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि तत्कालीन चौकी इंचार्ज राहुल तिवारी ने मनीष को लगभग खत्म करने के उद्देश्य से हिस्ट्रीशीट भी खोलने की पूरी तैयारी कर ली थी। परंतु, उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने पर एक निर्दोष की जान बच गई। (उक्त जानकारी मनीष द्वारा तथा घटना से संबंधित मिले सूत्रों के आधाार पर है)

पुलिस विभाग में जहां तमाम पुलिसकर्मी इतने भ्रष्ट और बेईमान होते हैं, वहीं विभाग में ईमानदार अधिकारियों की भी कमी नहीं है। पीड़ित मनीष बताते हैं कि वे महीनों की दौड़-भाग के बाद न्याय की आस पूर्ण रूप से छोड़ चुके थे, साथ ही वक्त की मार ने उनपर मानसिक रूप से ऐसा दबाव बनाया कि वे आत्महत्या करने की कगार पर आ कर खड़े हो गए। लेकिन, जब वे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे से मिले तो उन्होंने तत्कालीन डीसीपी उत्तरी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, सीओ अलीग. ंज राजकुमार व थाना प्रभारी अलीगंज फरीद अहमद को तत्काल जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने का आदेश दिया। आला अधिकारियों ने बात सुनकर न्याय दिलवाने का पूरा विश्वास दिलाया, साथ ही किसी भी रसूखदार द्वारा किए जा रहे अन्याय को बर्दाश्त न करने की भी बात कही।

योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते अधिकारी

स्वच्छ भारत मिशन व आवासों में घोर धांधली का पर्दाफाश

प्रफुल्ल गोस्वामी

केंद्र सरकार और सूबे की योगी सरकार द्वारा आम और गरीब जनता के लिए लाई जा रही योजनाओं में जिम्मेदारों द्वारा किए जा रहे एक बड़े घोटाले से जुड़ा हुआ मामला सामने आया, जिसका कम से कम और अधिक से अधिक लाभ भी आम जनता तक नहीं पहुँच रहा। गरीबों की योजनाओं के लिए आवंटित की जा रही धनराशि सीधे भ्रष्ट अधिकारियों की जेब तक पहुँच रही है। जिसकी जानकारी न जांच एजेंसियों को है और न ही शासन में बैठे अधिकारियों को। भ्रष्टाचार लोहिया आवास से जुड़े बड़े स्तर से लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे शौचालय तक निरन्तर होता जा रहा है। प्रदेश के हरदोई जिले में कई महीनों से लगातार हो रहे ऐसे ही घोटालों का सरकारी आंकड़ों के साथ स्वतंत्र स्वरूप के **उप-संपादक** द्वारा किया गया बड़ा खुलासा-

राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिला हरदोई के तहसील संडीला स्थित ब्लाक भरावन के गांव दूला नगर की एक ऐसी कहानी सुनने में आई, जिसे सुनकर एक झटके में यकीन कर लेना शायद ही मुमकिन होगा। परंतु, देखने पर आश्चर्य जरूर होगा कि क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकता है? लेकिन सही मायने में देखा जाए तो शासन और प्रशासन के लिए हर वह काम संभव होता है, जिसे सामाजिक व्यक्ति या यूं कहें कि एक आम नागरिक असंभव मानता है। भ्रष्टाचार से जुड़ी जिस कहानी का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, वह कहानी तो सिर्फ एक गाँव की है। यदि प्रदेश के सभी गावों में निष्पक्ष जांच कराई जाए तो 60 से अधिक प्रशासनिक अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर व आंखों पर काली पट्टी बांध कर असली भ्रष्टाचारियों का समर्थन व सहयोग करते हुए चंद कागज के सरकारी टुकड़ों पर बिना विचार किए हस्ताक्षर करने के साथ ही गांव की गरीब जनता को धोखा देते हैं। वही सूबे की सरकार का भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन का एक हिस्सा योगी सरकार की स्वच्छ व ईमानदारी की मंशा पर पानी फेर कर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से शासन व प्रशासन में बैठे कुछ राजनीति को खोखला करने वाले सिस्टम के दीमक लगातार सरकार की छवि को धूमिल करते चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यही लोग योगी आदित्यनाथ की स्वच्छ छवि, कुशल नेतृत्व व सख्त प्रशासनिक क्षमता वाली सरकार में सेंध लगाने में भी कोई कसर छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक ग्राम सभा दूलानगर के ग्राम प्रधान श्री कैलाश तथा गांव के तत्कालीन सचिव श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह पूर्व सपा सरकार में गरीबों के लिए चलाई गई आवास योजना (लोहिया आवास योजना) को तार-तार करते हुए गरीबों के घरों पर ही सेंध लगाते हुए उनके लाखों रुपए हजम कर गए। इतना ही नहीं, लोहिया आवास के तहत अंडर में आए आवासों का पैसा हड़पने के लिए नियम-कानून को भी ताक पर रखकर गैर जनपद में बसे अपने रिश्तेदारों के नाम से लेखपाल की मिलीभगत के चलते फर्जी निवास प्रमाण पत्र तहसील में बनवाकर व निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता से वोटर लिस्ट में फर्जी नाम (पूरे परिवार) के दर्ज कराते हुए अधिकारियों को विश्वास में लेकर केवल आवास का पैसा रखने के उद्देश्य से बैंक में फर्जी खाता खुलवा कर लगभग आधा दर्जन आवास बिना किसी निर्माण के हड़प लिए गए।

ग्राम प्रधान द्वारा अपने भाई आदि के नाम से पहले के बने कमरों/आवासों को फर्जी तरीके से बता कर सरकार से बड़ी रकम हड़पी गई। प्रधान द्वारा ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालयों को दूसरे गांव के रहने वाले लोगों के नाम

से दर्ज कराकर लाखों रुपयों का गोलमाल किया गया, दर्जनों शौचालयों को एक ही लिस्ट में दो से तीन बार दर्ज करा कर लाखों रुपए की हेराफेरी की गई और जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। साथ ही जो शौचालय बने भी हैं, वे मानक के अनुसार न बनकर आधे-अधूरे ही बने हैं। जानकारी के मुताबिक, दर्जनों शौचालय तो अभी तक बने ही नहीं है जिनका पैसा जिम्मेदारों के द्वारा फर्जी तरीके से हड़प लिया गया। जिनको शौचालय दिया भी है उनसे तयशुदा किस्त भी ली गई, जिसे कई लोग भय या दबाव के चलते अपनी दबी जुबान से कहते भी हैं।

लोहिया आवासों में भी यही प्रक्रिया अपनाते हुए रू. 20,000 से लेकर रू. 60,000 तक वसूले गए और जो आवास बने भी हैं उनमें से अधिकतर आवास पूर्ण व मानक के अनुसार न बने होकर आधे-अधूरे ही बनाए गए हैं। कुछ स्थानीय जागरूक जनता ने मामले की शिकायत जब जिम्मेदार अधिारियों से की तो सबसे पहले ग्राम प्रधान के गुर्गों द्वारा उन्हें जमकर पीटा गया, फिर परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी गई। साथ ही फर्जी मुकदमा दर्ज करा कर जेल भिजवाने की धमकी देते हुए कई ग्रामीणों को गांव से भगाने का प्रयास भी किया गया।

मामले से जुड़े मुख्य पात्रों को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार की योजनाओं के साथ जमकर खिलवाड़ करते हुए उन्हें लाभ देकर मुफ्त में आवास व शौचालय से लाभान्वित किया गया। मामले को अपने पक्ष में करने के लिए शिकायतकर्ताओं को हानि पहुंचाने के साथ मारपीट व धामकी आदि के सहारे जांच अधिकारियों को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हुए टीम वर्क की तरह काम किया गया। ग्रामवा. सियों ने बताया कि मामले की उनके द्वारा शिकायत करने पर उच्चाधिकारियों ने बिना किसी लज्जा के जांच उन्हें ही दे दी, जो स्वयं उक्त घटित कृत्यों में सारथी की भूमिका में थे। जिसके चलते गांव के कुछ लोगों द्वारा जब मामले की शिकायत की गई तो जांच करने आए जांच अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की एक बात भी सुनने से इनकार कर दिया, साथ ही दबाव डालते हुए कहा कि 'मैं केवल प्रधान की बात सुनूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो अपने द्वारा जांच की गई रिपोर्ट भी उनके पक्ष में ही लगाऊंगा। तुम लोगों को जो करना है कर लेना, किसी से भी शिकायत कर देना, कहीं भी चले जाना, जांच मेरे पास ही आएगी।' जांच अधिकारियों के साथ में आए पुलिसकर्मियों ने धमका कर मामले से पूरी तरह से दूर रहने को कहा साथ ही यह भी कहा कि 'सरकारी जांच में बाधा पहुचांने की बात कहकर तुम लोगों को जेल में बंद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।' कुछ देर बाद ही शिकायतकर्ता व कुछ ग्रामीणों को शिकायत करने की बात पर थाने में बुला लिया गया और पुलिसवालों द्वारा जम कर पिटाई कराई गई, जिसके बाद से हर कोई शिकायत करने से घबरा रहा है।

ऐसी घटनाओं के घटित होने से हर कोई अचंभित रह जाता है कि योगी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जो पूर्व की सभी सरकारों के भ्रष्टाचार को पीछे छोड़ चुका है। जिसका मुख्य कारण सिस्टम में बैठे वे सरकारी कीड़े हैं जो सरकार की योजनाओं को दीमक की तरह धीरे-धीरे खत्म करने के उद्देश्य से काम करते हुए सरकार को अपमानित करने का निरन्तर प्रयत्न करते जा रहे हैं और यदि कोई इनके भ्रष्टाचार की आवाज उठाता भी है तो उसे वर्दीधारियों की मदद से जेल में बंद करा दिया जाता है। प्रशासन के चंद अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थों के द्वारा किए गए अपराध को छिपाने व और अधिक करने का भरपूर मौका देते हैं। थक-हार कर पीड़ित जनता मार खा कर बैठ जाती है और सरकार को चुनाव में कर्मों की सजा देने के लिए तैयार हो जाती है। जिसका विपक्षी दल भी पूरा फायदा उठाते हैं।

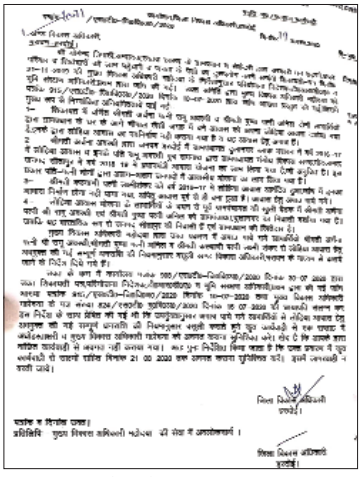
स्वतंत्र स्वरूप टीम की मुहिम का असर

घटना से संबंधित ग्रामसभा दूलानगर के जगदीशपुर निवासी सुरेंद्र तिवारी ने जिलाधिकारी हरदोई को एक शपथपत्र देकर ग्रामसभा में हो रहे लाखों के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए शिकायत की। लेकिन डीएम साहब ने मामले की जांच उन्हें ही सौप दी, जो इस बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सरकारी नीतियों को लगातार चूना लगाते चले आ रहे थे। मौके पर मीडिया के सामने उन्होंने जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायत को यह कहकर सुनने से इनकार कर दिया कि 'मैं जांच करने आया हूं, शिकायत सुनने नहीं। मैं सिर्फ प्रधान से बात करूंगा और उनकी की बात सुनूंगा।' वे ग्राम प्रधान कैलाश का पक्ष लेते हुए फर्जी आवासों को बचाने का मार्ग बता कर चले गए।

शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम प्रधान की सगी साली पुष्पा जो कि ग्राम सभा पुर (अहेवा) जनपद सीतापुर की रहने वाली हैं। वहां विधावा पेंशन सहित इंदिरा आवास व स्वच्छ मिशन के अंतर्गत शौचालय व अंत्योदय राशन कार्ड जैसी सरकारी सुविधाओं का लगातार लाभ ले रही हैं।

पुष्पा का आधाार कार्ड संख्या- 8302 699 50986
विधानसभा मतदाता सूची संख्या- ZKW 0716654 तथा ग्राम

कथित अर्चना अवस्थी पत्नी रामू अवस्थी प्रधान की रिश्तेदार के नाम से फर्जी आवास का आंवटन करके तथा रामू अवस्थी के शौचालय का धन हड़पा गया।

पुष्पा पत्नी अनिल कुमार निवासी जनपद सीतापुर जिनके नाम से आवास व शौचालय का कथित रूप से पैसा हड़पा गया।

मतदाता सूची में क्रमांक 316 में नाम दर्ज है।

पुष्पा का अंत्योदय कार्ड संख्या- 2154 20743 634 है तथा इनका बैंक खाता 'भारतीय ग्रामीण बैंक' की शाखा नीलगांव जनपद सीतापुर है। जिसमें विधवा पेंशन आधारित होती है। इनका 'परिवार रजिस्ट्रेशन संख्या' 133 है जो कि पृष्ठ संख्या 124 पर उपलब्ध है। इनका सिधौली तहसील से बनवाया गया निवास प्रमाणपत्र संख्या- 24 6202001975/दिनांक 4/02/20 है। साथ ही पुष्पा की विधवा पेंशन सूची ग्राम हरदोई से क्रमांक 14-31 2910 15527 है। पुष्पा का नाम इंद्रा आवास योजना में क्रमांक संख्या- 32 सभापुर अहेवा में भी दर्ज है।

पुष्पा को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त शौचालय की जानकारी अहेवा की सूची में क्रमांक- 67 तथा फैमिली आईडी संख्या- 9921 5771 पर दर्ज है। उक्त साक्ष्यों के बावजूद ग्राम प्रधान दूलानगर अपने सेक्रेटरी, लेखपाल, निर्वाचन कर्मी एवं बी. डी.ओ भरावन की मिलीभगत से फर्जी कागजात तैयार कर इनके नाम ग्राम सभा में बिना निर्माण के लोहिया आवास के लाखों रुपए हड़प लिए गए तथा शौचालय दूलानगर की सूची में क्रमांक संख्या-16 व फैमिली आईडी कार्ड संख्या- 6385 3925 है। यहां भी शौचालय के लिए प्राप्त किए गए लाखों रुपए अधिकारियों की मिली भगत से हड़पे गए।

मामले की शिकायत करने पर जांच के लिए आए जांच अधिकारी को ग्राम प्रधान ने अपने पूर्व के बने मकान के एक

मास्क के नाम पर गुण्डागर्दी

बलिया (उप्र)। सूबे की बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ सरकार में बैठे कुछ अधिकारी जो सरकार को बदनाम करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर जनता में छवि खराब कर रहें हैं। बलिया के बेल्थरा रोड़ तहसील के एसडीएम अशोक चौधरी ने लोगों को मास्क न लगाने पर सरेआम पुलिस बल का प्रयोग करते हुए खुद लाठी लेकर आम जनता व समाज के इज्जतदार लोगों को लाठी-डंडों से बुरी तरीके से पीटकर सरकार की छवि को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उक्त घटना में कई लोगों का हाथ भी जख्मी हो गया।

एसडीएम अशोक चौधारी ने लाठी-डंडों से पीटते हुए बुजुर्गों और महिलाओं का भी ख्याल नहीं रखा जबकि मास्क न लगाने पर राज्य सरकार ने जुर्माने का प्रावधान रखा है तथा मास्क न होने की स्थिति में आप रुमाल या गमछा का प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज की प्रेरणा खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दी थी। इस तरह एक एसडीएम का रोड पर उतर कर कानून को अपने हाथ में लेते हुए खुलेआम गुंडई करना कही ना कही योगी सरकार के खिलाफ की गई एक सोची समझी साजिश को दर्शाता है योगी सरकार ने एसडीएम अशोक चौधरी के इस क्रूर कृत्य को संज्ञान में लेते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

वाहन चेकिंग के नाम पर ग्रामीण पर टूटा पुलिस का कहर

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के थाना मसौली के बांसा गांव के निकट स्थानीय पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों पर अपनी मर्दांगनी दिखाते हुए जमकर लूट-घसोट के साथ कहर बरपाया। इसी कड़ी में पुलिस वालों की घोर लापरवाही का निशाना एक सीधा-साधा ग्रामीण कथावाचक बन गया। वह अपने किसी निजी काम से जा रहा था, पुलिस वालों ने उसको रोक लिया, फिर गाड़ी के कागजात दिखाने को बोला, वह गाड़ी के कागजात दिखाने लगा इसमें से एक कागज उसके पास ना होने की स्थिति में उसने पुलिस को समस्या बताई इस पर पुलिस वाले उससे बेहद कड़े अंदाज में गाली गलौज करने लगे। जबकि परिवहन अधिनियम के अंतर्गत गाड़ी के पूरे कागजात ना मिलने पर चालान काटने का प्रावधान है, पुलिस ने उस ग्रामीण पर लाठी-डण्डों का कहर बरपाते हुए उसे लाठी डंडों से मारने लगे उसको इतना बेरहमी से पीटा गया, उसके शरीर पर गहरे जख्म के निशान पड़ गये। इस तरह की क्रूरता देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे कि वह साधारण ग्रामीण ना होकर कोई तस्कर या इनामी बदमाश हो।

उक्त घटना से क्षेत्र में सरकार की छवि को दागदार करने के लिए भ्रष्ट पुलिस वालों पर कोई कार्यवाई न होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है तथा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों वा पुलिसवालों के कृत्यों से जनमानस के जेहन में सरकार की छवि काफी खराब की जा रही है।

हिस्से को योजना के तहत बताकर जनता व शासन को लगातार गुमराह किया जा रहा है।

कोई अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि पूर्व के बने एक कमरे और लोहिया आवास में क्या अंतर होता है? फिर भी जांच अधिकारी को सरकारी कागज पर संतुष्ट कर दिया गया। यह बहुत ही हास्य पद एवं शर्मनाक है।

दूसरा उदाहरण दूलानगर के ग्राम प्रधान की सगी सरहज जो कि ग्रामसभा गंगोय ब्लॉक गोंदलामऊ जनपद सीतापुर की स्थाई निवासी हैं। **जिनका ग्राम में-**

आधार कार्ड संख्या-93 80 94530 410

राशन कार्ड संख्या- 2154 4021 7422

परिवार रजिस्ट्रेशन संख्या- 393

मकान नंबर-155 पर दर्ज है। इनका वोटर कार्ड संख्या ZKW05 91727 व तहसील सिधौली द्वारा बनवाए गए निवास प्रमाण पत्र की संख्या 24 620 2000816 दिनांक 16/1/2020 है। इसी प्रकरण में इनके पति रामू अवस्थी का नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सूची में UP1034 992 दर्ज है। गांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने शौचालय से सभी लाभांवित हैं, इनके बच्चे परिवार सहित गंगोय में रहकर पड़ोसी गांव में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

अर्चना अवस्थी जो कि ग्राम प्रधान की सरहज हैं, उनके इतने साक्ष्य होने के बावजूद ग्राम प्रधान अपने सेक्रेटरी, लेखपाल, तहसीलदार, निर्वाचनकर्मी तथा बी.डी.ओ भरावन व एस.डी.एम की मिलीभगत से कानूनी नियमों को तांक पर रखकर फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र व निर्वाचन नामावली में नाम सहित तमाम फर्जी कागजात तैयार कर बैंक ऑफ इंडिया शाखा भटपुर हरदोई में खाता खुलवा कर अर्चना अवस्थी के नाम का फर्जी तरीके से बिना निर्माण के पैसा निकाल लिया। इनके पति रामू अवस्थी के नाम का भी दूलानगर में बिना शौचालय निर्माण के शौचालय का पैसा निकाला गया। (शौचालय सूची संख्या-19 पर दर्ज)

उक्त ग्राम सभा में नीचे स्तर से लेकर जिले के सबसे ऊचें स्तर तक सभी जिम्मेदारों द्वारा अपना-अपना तयशुदा हिस्सा लेकर लगभग डेढ़ दर्जन शौचालयों का पैसा बिना बनवाए बंदरबांट किया गया। दर्जनों नाम ऐसे भी हैं जो कि दूसरे गांव से संबंधित हैं। उन लोगों के नाम दर्ज कर पैसा निकाला गया और जो शौचालय बनवाए भी गए हैं वे मानक के अनुरूप न होकर बेहद खराब स्तर के बनाए गए।

दर्जनों अपात्रों को आवास व शौचालय का लाभ देकर पात्र व गरीब को सरकारी योजनाओं से दूर रखा गया। उक्त शिकायत की जांच करने आए श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव व PD ने शिकायतकर्ता को मीडिया के सामने धामकी देते हुए यह तक कहा कि 'जांच हमें ही करनी है इसमें हमारे साहब सहित कई लोग फंस सकते हैं। अत: मामले में अधिक दखल मत दो या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहो।'

यह तो मात्र एक ग्रामसभा के भ्रष्टाचार की बानगी है, इसी ग्राम सभा में नियम को ताक पर रखकर अपने भाई सहित कई अपाजों को फर्जी तरीके से सरकारी योजना के तहत आने वाले आवासों का लाभ दिया गया, उन्ही आवासों में भूसा भरा देखकर जांच अधिकारी ने इसे जांच में सम्मिलित नहीं किया। मानक के अनुरूप नहीं बने आवासों को भी जांच अधिकारी ने सही बता कर आरोपियों को बचने का पूरा रास्ता दिया।

ऐसे भ्रष्ट लोगों की वजह से पूरी सरकार बदनाम हो रही है। यदि उक्त प्रकरणों की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए तो दर्जनों भ्रष्टाचारी, जो पूरे सिस्टम को खत्म करने पर तुले हुए हैं, उन्हें दंडित करके पूरे सिस्टम को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। सरकार और समाज को इस पर ध्यान देने की शख्त आवश्यकता है।

शौचालय राम नरेश सिंह

शौचालय नवल किशोर ग्राम सभा दुलापुर

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ग्राम दुलानगर के प्रधान व उनके साथ संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का दंड भुगत रहे ग्रामवासियों ने जब मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की तो शिकायत करने के लगभग ३ से ४ वर्ष व्यतीत होने बाद पूर्व में जो शौचालय नहीं बने थे और जिनका पैसा भ्रष्टाचारियों द्वारा हड़प लिया गया था, उनकी जांच उच्चाधिकारियों द्वारा कराई गई। इस भ्रष्टाचार की जांच में हुए खुलासे में पाए गए आरोपी व अधिकारियों के साथ अन्य संलिप्त भ्रष्टाचारियों की मिली भगत से प्रधान द्वारा गोपनीय रूप से सैकड़ों शौचालय बनाए जाने का कार्य शुरू हो गया। अचानक शौचालय बनाने का कार्य सिर्फ इस उद्देश्य से शुरू किया गया ताकि, पूर्व में हुई जांच को गलत साबित करते हुए आरोपियों को मामले से बचाया जा सके।

देश को मिली नई एजुकेशन पॉलिसी

स्कूल से लेकर पीएचडी तक होंगे ये बड़े बदलाव

दिव्या गौरव त्रिपाठी

बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह बात को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। यह बदलाव इसरो प्रमुख श्री कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य बताएंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विशेषताएं।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की है। जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा (Medical and law studies not included) पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में शामिल था।

नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार के माधयम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे संशोधन किए हैं। जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत छात्रों को अब कोई एक स्ट्रीम नहीं चुननी होगी। अब छात्र आर्ट स्ट्रीम के साथ साइंस स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के साथ आर्ट्स स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम ना मान के पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा, जिसमें योग, खेल, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत आदि शामिल है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा जिससे कि छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चार चरण

नई शिक्षा नीति को चार चरणों में विभाजित किया गया है जो कि 5+3+3+4 पैटर्न है। इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा शामिल है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सरकारी तथा प्राइवेट दोनों

संस्थानों को फॉलो करना होगा। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चार चरण कुछ इस प्रकार है।

फाउंडेशन स्टेज

फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए हैं। जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा (कक्षा एक तथा दो) शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रिप्रेटरी स्टेज

प्रिप्रट्री स्टेज के अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे। जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल है। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।

मिडिल स्टेज

मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी।

सेकेंडरी स्टेज

सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स स्ट्रीम लेते थे। परंतु अब यह खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स का या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स के भी ले सकते हैं।

B-Ed अब 4 साल का

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बीएड को 4 साल का कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का बी एड प्रोग्राम होगी। सभी स्टैंडअलोन शिक्षण संस्थान जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वोकेशनल स्टडीज पर फोकस

हमारे देश में वोकेशनल स्टडी सीखने वाले छात्र 5% से भी कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों को वोकेशनल स्टडीज सीखने पर ध्यान दिया जाएगा। जिसमें बागबानी, लकड़ी का काम, मिटी के बर्तन, बिजली का काम आदि शामिल है। 2025 के अंत तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 50% छात्रें को वोकेशनल स्टडीज पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा

जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह बात को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। अब शिक्षकों को पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना का प्रयास किया जाएगा और यदि पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में बच्चों और शिक्षक के बीच बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगी। कक्षा एक से बच्चों को दो से तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी।

शिक्षकों की भर्ती

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यदि दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों की कमी है। इस स्थिति में विशेष तौर से प्रयास किए जाएंगे की दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों को भर्ती कि जाए। जिसके अंतर्गत रिटायर हुए शिक्षकों को भी दोबारा से बुलाया जा सकता है।

विदेशी भाषा सिखाई जाने पर भी जोर

माधयमिक विद्यालय में बच्चे अपने पसंद की विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं। जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीस, जैपनीज आदि होंगी। यह सभी प्रयास भारत की शिक्षा को वैश्विक तौर पर पहचान बनाने का एक प्रयास है।

नई नीति में MPhil खत्म

देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम फिर MA और उसके बाद बिना M-Phil के सीधा PhD कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

नई शिक्षा नीति के लाभ

- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा।
- पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा। छात्र अगर चाहे तो यह भाषाएं पढ़ सकते हैं।
- बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि साल में दो बार छात्रों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं ली जाए।
- पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा।
- हायर एजुकेशन से एमफिल की डिग्री को खत्म किया जा रहा है।
- एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सिलेबस में रखा जाएगा।
- छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगी जो कि राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिससे कि यह पॉलिसी सुचारू रूप से चल पाए।
- नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेता है तो वह पहले कोर्स से निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।

एक पहल: पिता के सपनों को पंख लगाकर किसानों को दी नई जिंदगी

दीपिका

हमारे देश के किसानों के लिए असली सोना, उनकी असल पूंजी, उनकी पैदावार है। भारत को तो शुरू से कृषि प्रधान देश के नाम से जाना ही जाता है। सम्पूर्ण भारत में लॉक डाउन की भयावह स्थिति ने हम सब को अंदर से तोड़ कर रख दिया है लेकिन इन सब के बीच हमें खाने की कमी नहीं हुई। क्योंकि बाकी सब कोरोना योद्धाओं के जैसे हमारे किसान भी बड़ी शिद्दत से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे किसान कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसानों को उनकी मेहनत का असल मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने की दिशा में और साथ ही उन्हें और अच्छी फसल के लिए प्रेरित कर रहे है, बिहार के वैशाली जिला के प्रियांशु राज।

प्रियांशु मूलत: बिहार के वैशाली जिले के रसलपुर गाँव के रहने वाले एक आम किसान परिवार के कर्मठ युवा किसान हैं। इन्होंने अपनी पूरी पढाई जयपुर से की है और अभी फिलहाल एम बी ए भी जयपुर से ही कर रहे हैं। लॉक डाउन में कॉलेज बंद हो जाने के कारण ये वापिस अपने गाँव यानि बिहार आ गए और यहां से इन्होंने शुरुआत की अपने पिता के सपनों को एक नयी उड़ान देने की दिशा में काम करने की। प्रियांशु के पिता, कामेश्वर सिंह कुशवाहा ने अपनी पूरी जिन्दगी अपने देश और अपने किसानों को समर्पित कर दी है। सन 2007 में, बिहार सरकार द्वारा कामेश्वर सिंह को किसान श्री सम्मान से सम्मानित किया गया और साथ ही 1 लाख की इनाम राशि भी दी गयी है। कुल मिलाकर कहें तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल कर समाज और देश के लिए कुछ करने का सपना लिए प्रियांशु ने अपना स्टार्ट अप शुरू किया है।

प्रियांशु की कहानी उनकी ही जुबानी: '2014 में आगे की पढाई के लिए मैं जयपुर आ गया और यहां एपेक्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बी.टेक की पढाई पूरी की। 2018 में बी. टेक करने के बाद मैंने आईसीआईसीआई फाउंडेशन में विकास अधिकारी के रूप में काम करना शरू किया। मेरा रुझान शुरू से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का था। वहाँ के लोगों को हमने कौशल विकास के तहत उनको प्रशिक्षण दिया। महिलाओं को जागरूक करते हुए, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। साथ ही उनके लिए उनके अनुसार रोजगार भी दिलाया। इस तरह से हम ग्रामीण विकास कर देश की तरक्की में योगदान कर सकते है।'

लॉक डाउन में घर आना कारगर साबित हुआ: प्रियांशु के अनुसार, होली की छुट्टियों में घर आना हुआ। लेकिन लॉक डाउन की वजह से वापिस जा नहीं पाए, इसलिए यहीं रहकर अपने गाँव के लिए कुछ करने की सोच के साथ - FPO यानि FARMER PRODUCER ORGANISATION LIMITED से जुड़ गए और बतौर सी.ई.ओ. रसलपुर तुर्की प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में काम करना शुरू किये। प्रियांशु शुरू से अपने पिता के सपने को ही अपने लक्ष्य मानते आये हैं, और इनके पिता

जिन्दगी तो ऊपरवाला देता है लेकिन उस जिन्दगी को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। एक तरफ इस कोरोना काल में जहां लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, प्रशासन, और भी कई समाज सेवक सेविकाएं एक योद्धा की तरह दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं।

कामेश्वर सिंह कुशवाहा का यही सपना है कि हर किसान को उनकी मेहनत के अनुसार उचित मूल्य मिले, जिससे उनकी भी आजीविका सुचारु रूप से चल सके।

एफ. पी. ओ. के बारे में : दरअसल एफ. पी. ओ. कंपनी यानी FARMER PRODUCER ORGANISATION लिमिटेड की शुरुआत प्रियांशु के पिता ने अपने गाँव के 10 किसानों के साथ मिलकर की थी। ये एक गैर सरकारी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक पहल है। सन 2002 में कामेश्वर सिंह जी को किसान मित्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था. वैसे तो शुरू से इनका लक्ष्य था की किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। इस उपाधि से सम्मानित होने के बाद कामेश्वर जी ने इस दिशा में काम करना और तेजी से शुरू कर दिया। इन्होने भारत सरकार की एन.जी.ओ. 'आत्मा' के साथ जुड़कर और जिला कृषि पदाधिकारी के साथ मिलकर छोटे और पिछड़े वर्ग के किसानो को प्रशिक्षण देना शुरू किया। इससे बड़ी तादाद में किसान जुड़ते चले गए और जैविक खेती के बारे में जाने लगे. लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आना था। 2019 में कामेश्वर जी ने अपने प्रखंड के किसानो के साथ मिलकर FARMER PRODUCER ORGANISATION लिमिटेड के तहत रसलपुर तुर्की प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की और लगभग 400 किसानो के साथ जुड़कर जैविक खेती की शुरुआत की। इन्हें उचित प्रशिक्षण देकर शुन्य बजट पर खेती करना शुरू करवाया और जितनी भी पैदावार किसानों के माध्यम से हुई, उनका उचित मूल्य उन्हें देकर उनकी आय में वृद्धि कराई।

डिजिटल मार्केटिंग काफी मददगार साबित हुई: किसानों की मेहनत और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से इन लोगों ने न सिर्फ बिहार में, बल्कि दक्षिण और पश्चिम भारत में भी अपने फलों और सब्जियों का निर्यात किया। इसके कारण किसानों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और पूरी शिद्दत से उन्होंने काम को और बढ़ाने की कोशिश में जुड़ गए। कोरोना के इस दौर में जहां एक तरफ सभी हताश और परेशान थे अपनी नौकरी और काम को लेकर, वहीं दूसरी तरफ ये किसान दिन रात मेहनत कर हमारे लिए खाने की चीजों को उगा रहे हैं, ताकि किसी भी भारतीय को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन सब में डिजिटल और नयी तकनीक ने इनकी काफी मदद की। प्रियांशु के अनुसार, 'सोशल मीडिया की मदद से हमने सबसे पहले अपने उत्पादों का विज्ञापन करना शुरू किया। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस अच्छे से सभी खाद्य उत्पादों को कार्टून में पैक कर ट्रांसपोर्ट में डाल देते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं की वो जल्द से जल्द सही समय में उपभोक्ताओं के पास पहुँच जाये। इसके लिए हम निरंतर ट्रैकिंग करते है और दिए गए समयावधि पर सामान पहुंचाते हैं।

कामेश्वर सिंह कुशवाहा से खास बातचीत: 'किसान चाहे बड़ा हो या छोटा, मेहनत उतनी ही करता है जितनी सभी करते

हैं। लेकिन किन्ही कारणों से उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। ये एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मुहीम शुरू की और इसमें बिहार सरकार में हमारी बहुत मदद की। अभी तक 360 किसानों को 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार द्वारा दी जा चुकी है, जिससे वे अपनी खेती सुचारु रूप से कर पा रहे हैं और भारत की तरक्की में अपना योगदान भी दे रहे है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि, इस काम में महिलाएँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और एक सफल किसान बन कर अपनी और अपने परिवार की जीविका चला रही हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब हम महिलाओं को पूरी सजगता और कर्मठता के साथ खेती करते देखते हैं। आज हमारी किसान बहनों के कारण, पूरा समाज ताजी और शुद्ध फलों और सब्जियों का सेवन कर पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है की हर किसान की आय दोगुनी होगी, उनके इसी सपने को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर लगे हुए हैं और हमें विश्वास है आने वाले एक वर्ष के अंदर हम उनके इस सपने को भी पूरा कर देंगे।

एक सफल महिला किसान की सफल कहानी: 'मेरा नाम रेखा देवी हैं। हम पिछले एक साल से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे से खेती कर अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद हम और अच्छे से खेती कर पा रहे हैं और खुशी है कि अपनी मेहनत का हमें उचित मूल्य मिल रहा हैं। हमें अब मंडी जाकर दिन भर सब्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अच्छी तरह से सब्जियों की खेती कर एफ. पी. ओ. को देते हैं और हमें उसका उचित मूल्य मिल जाता है. इससे हमें कहीं जाने की परेशानी नहीं होती और हमारा सामान भी सुरक्षित रहता है।

भविष्य के बारे में पूछने पर रेखा देवी ने कहा कि उनकी बेटी आगे पढ़ना चाहती है। पहले सोचा था कि नहीं पढ़ा पाएंगे लेकिन अब सरकार की मदद और एफ. पी. ओ. के साथ जुड़ कर अपने बच्चों के सपने को पूरा जरूर करेंगे।

जिन्दगी तो ऊपरवाला देता है लेकिन उस जिन्दगी को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। एक तरफ इस कोरोना काल में जहां लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, प्रशासन, और भी कई समाज सेवक सेविकाएं एक योद्धा की तरह दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान भाई बहन पूरी कर्मठता से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उचित और जैविक खेती के माध्यम से शुद्ध खाने की चीजें हम तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी इस सेवा को हम किसी भी तराजू में तौल नहीं सकते। हाँ! इतना जरूर कर सकते हैं कि इनकी नि:स्वार्थ सेवा और कर्मनिष्ठा के लिए हम सभी भारतवासी इन्हें नमन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं की इनकी मदद से हम और हमारा परिवार शुद्ध और प्राकृतिक चीजों का सेवन कर पा रहे हैं।

अस्पताल बना लूट का अड्डा

महापुरुषों के नाम को बदनाम करता राजधानी का नामी संस्थान

प्रखर ओमर

स्वामी विवेकानंद अस्पताल मरीज को वह सुविधा भी नहीं जाती जो सुविधाएं आम तौर पर सर्वसुलभ होती हैं। प्रबंधतंत्र की मनमानी के चलते मरीजों से इलाज के नाम पर मनमाने तौर से वसूली की जाती है।

आज जहां पूरी दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे योद्धा निरन्तर बिना हिचकिचाहट के अपने फर्ज को अंजाम दे रहे है। पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहे है हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी। इस समय सरकार के सामने कई चुनौतियाँ है और हर मुश्किल का सामना हमें मिल कर करना है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो है हमारे स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मचारी। डॉक्टर्स और बाकी के मेडिकल स्टाफ, इस कोरोना के युद्ध में सबसे आगे खड़े हमारे योद्धा हैं। पिछले 78 दिनों से हम सभी अपने घरों में लॉक डाउन हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मी चौबीसों घंटे हमारी सेवा के लिए डट कर खड़े हैं। इतनी जबरदस्त गर्मी में भी पी.पी.ई किट्स पहन कर हमारे स्वास्थ्य कर्मी पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। देश भर के लाखों डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स दिन रात हमारी जिन्दगी को बचाने में लगे हुए हैं।

लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जिन्दगी में हमें भी अलग अलग तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। एक तरफ कई डॉक्टर्स निश्छल भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजो के शोषण की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसमें एक ताजा उदाहरण नोएडा का है जहाँ एक पिता अपने नवजात बच्चे को 6 घंटे तक रोड पर लेकर घूमता रहा लेकिन 4 निजी अस्पताल जाने के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। इस तरह की लापरवाही की खबरें सुनकर दिल दहल जाता है कि कुछ चिकित्सा माफिया कुछ पैसे के लालच में इंसान की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। धरती पर ईश्वर के रूप में पूजे जाने वाले डॉक्टर्स, न जाने कब दानव के रूप में परिणत हो गए। जान बचाने वाले, जाने लेने वाले हो गए। हमारी संस्कृति में शुरू से दूसरों की मदद करने, दूसरों की सेवा करने और दूसरों के दुखों को कम करने की सिख हमें दी है। फिर आज थोड़े से पैसे की खातिर हम क्यों अपनी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं?

अस्पतालों की लापरवाही के क्रम में हम आपको लखनऊ स्थित स्वामी विवेकानंद अस्पताल की घटना के बारे में बता रहे हैं। लखनऊ के मालवीय नगर के संजय श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को लीवर संबंधी समस्या हुई। उनके परिवार ने उनको स्वामी विवेकानंद अस्पताल में ले जाना सही समझा। परिवार ने सोचा ट्रस्ट का अस्पताल है, तो आर्थिक बोझ भी थोड़ा कम हो जायेगा। इन सब बातों को सोचकर वे मरीज को लेकर स्वामी विवेकानंद अस्पताल पहुँच गए। लेकिन वहाँ पहुँचकर शुरुआत से सारी चिकित्सकीय प्रकिया उम्मीद के मुताबिक नहीं लग रही थी लेकिन कोरोना के कारण कुछ दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा था। मरीज की सही वस्तुस्थिति के बारे में भी डॉक्टर्स उनके परिवार को कुछ नहीं बता रहे थे। कुछ समय उपचार के बाद जूनियर्स डॉक्टर्स ने परिवार पर मरीज के डायलिसिस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

मरीज के छोटे भाई अजय श्रीवास्तव ने स्वतंत्र स्वरूप टीम से बात करने पर बताया कि जब तक परिवार के लोग अस्पताल

में रहते थे तब तक सब कुछ ठीक बताया जाता था लेकिन जैसे ही परिवार के लोग घर पहुँच जाते थे फिर डॉक्टर्स मरीज की हालत गंभीर बताने लगते थे। एक तो कोरोना के कारण सभी पर आर्थिक मार तो पड़ ही रही है, उस पर से डॉक्टर्स का इस तरीके के व्यवहार ने परिवार का और बुरा हाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रस्ट का अस्पताल न होकर एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें अपने कर्मचारी रूपी डॉक्टरो को अपना टारगेट पूरा करना है। डॉक्टर्स ने सभी जरूरी तथा गैरजरूरी टेस्ट भी करा लिए थे। मरीज संजय श्रीवास्तव के 2 बच्चे भी हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उन्ही पर है। ऐसे में उन्हें कुछ भी हो जाए तो उनके परिवार के लिए कितना बुरा होगा, ये शायद ही हम और आप या वहाँ के डॉक्टर्स समझ पाते। परिवार के सभी सदस्य डॉक्टर्स के इस रवैये से काफी आहत और निराश हो गए। कुछ समय के बाद डॉक्टर्स डायलिसिस का दबाव बनाने लगे। हद तो तब हो गयी जब रिपोर्ट्स को लेकर परिवारजन ने अपने परिचय के कुछ डॉक्टर्स को दिखाया और तब पता चला कि डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि स्वामी विवेकनद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स डायलिसिस का दबाव डाल क्यों रहे थे? ट्रस्ट का अस्पताल होने के बावजूद भी हर दिन दवाइयों का बिल 5 हजार के ऊपर जा रहा था। कोई भी डॉक्टर्स सही से बात नहीं कर रहा थे। लॉक डाउन में हर दिन 10 हजार के ऊपर बिल चुकाने के बाद भी मरीज की सही स्थिति के बारे में कुछ ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने रूखे मन से डायलिसिस के लिए मना कर दिया। परिवार जन ने इन सब अव्यवस्थाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की, पर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। फिर डॉक्टर्स ने मरीज के लीवर में पानी जमा होने की कुछ समस्या बताई। लेकिन साथ में सीनियर डॉक्टर्स के अस्पताल न आने की बात भी कहने लगे और मरीज का इलाज करने में असमर्थता दिखाने लगे। अस्पताल ने परिवार के सामने अब और भी बुरी स्थिति ला खड़ी कर दी। अस्पताल का कहना था सीनियर डॉक्टर्स अस्पताल आना नहीं चाहते हैं। सीनियर डॉक्टर्स अपने मरीज की समस्या दूर करने के लिए अस्पताल नहीं आना चाहते है ये सब देखकर परिवार जन की हालत और भी बुरी हो गयी। स्वामी विवेकानंद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें किसी और अस्पताल में ले जाने को कह दिया। ऐसे गंभीर समय में अस्पताल मरीज की समस्या को कम करने के बजाय उनकी मजबूरी में लूट का खेल करने में व्यस्त था। फिर जैसे तैसे एक दूसरे नामी अस्पताल में रेफर के लिए व्यवस्था की गयी। फिर से परिवार पहले जैसे स्थिति में आ गया, जहाँ से इलाज शुरू हुआ था। मरीज के भाई अजय श्रीवास्तव ने बताया कि स्वामी विवेकानंद अस्पताल ने वह सुविधा भी नहीं दी जो सुविधायें मरीज को आसानी से दी जा सकती थी। परिवारजन ने स्वामी विवेकानंद अस्पताल की इस लापरवाही की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात कही है। इस समय मरीज का उपचार दूसरे अस्पताल में चल रहा है तथा परिवारजन वहां के उपचार से संतुष्ट हैं। लॉकडाउन के समय ऐसे अनेकों परिवार हैं जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के लालच के शिकार बन रहे हैं। इनके लिए मानवीय मूल्यों कि कोई अहमियत नहीं होती। इंसान भी अंत में हार मान जाता है, जब यही हमारे रक्षक, हमारे भक्षक बन जाते हैं। एक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करने में गुजार दी। उनका मानना था की जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाये, तब तक रुकना नहीं है। लेकिन आज यही अस्पताल जो उनके नाम से जाना जाता है, चंद रुपयों के लिए रुक गया। डॉक्टर बनने के बाद व्यक्ति की असली पहचान उनके मरीजों के चेहरे पर आई खुशी से ही हो जाती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद अस्पताल के मरीजों और उनके परिवरों के चेहरे पर की निराशा ये साफ बता रही है की हर इंसान डॉक्टर तो बन सकता है लेकिन हर डॉक्टर इंसान नहीं बन सकता है। सरकार को तत्काल ऐसे ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

राजधानी लखनऊ में स्वामी विवेकानन्द अस्पताल के नाम से मशहूर अस्पताल में दूर-दूर से एक विश्वास लेकर लोग आते हैं कि उक्त संस्थान में कम पैसों में अच्छा इलाज हो जाएगा परंतु यहां भर्ती कराने के बाद जिस तरह से मरीजों व पीड़ितों के साथ शोषण व दोहन का कार्य होता है, उसे देखकर विश्वास उठ जाना एक मरीज के लिए लाजमी बनता है। संस्थान में कुछ मरीजों ने बताया कि सर दर्द और उल्टी आदि की समस्या के चलते दिखाने पर गंभीर समस्या बताकर भर्ती कर लिया गया, जहां भारी रकम देने के साथ शोषण भी हुआ। हर वह जांच कराई गई, जिसकी शायद ही कोई आवश्यकता होती परंतु हर जांच में कुछ भी समस्या ना आने के बावजूद भी लगभग 15 दिनों की भर्ती की गई। मरीज की आईडी संख्या IP/19/000885 है जो कि डॉ. जावेद अहमद की देखरेख में इलाज शुरू किया गया, लगभग हर दिन कोई ना कोई जांच की गई तथा जांच के नाम पर काफी रुपया भी वसूला गया। सभी जांचों में कुछ भी खास नहीं मिला, फिर भी हजारों रुपए जांच व इलाज के नाम पर मरीज से ले लिए गए।

मरीज को जिस वार्ड में भर्ती किया गया था, उसी वार्ड में बेड के पास एक गंभीर टीबी के मरीज को भी भर्ती कर वार्ड के सभी मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उस वार्ड में आए टीबी के मरीज आशीष जिनके मुंह के साथ शरीर के अन्य भागों से बहुत अधिक खून बह रहा था। रात भर वार्ड के सभी मरीज उक्त टीबी मरीज की व्यथा देख कर सो नहीं पाते थे। टीबी मरीज के बेड के पास कूलर व सीलिंग फैन चलने से मरीज के खांसने से वार्ड में संक्रमण का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था, सभी पीड़ित मरीज वार्ड से बाहर निकल कर अपना समय बिता रहे थे। काफी शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रशासन नहीं चेता तथा तीसरे दिन उस टीबी मरीज की मृत्यु हो गयी। ऐसे लापरवाह अस्पताल प्रशासन की हरकतों से तंग आकर पीड़ित मरीज को परिवारजनों ने अस्पताल को समस्त भुगतान कर मरीज की छुट्टी करा ली।

मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने पर उन्होंने भी अभद्रता करते हुए पीड़ित के परिजनों को यह कहते हुए भगा दिया कि तुम्हें यहां किसी ने बुलाया नहीं था, आए क्यों? दुबारा मत आना, जो करना चाहते हो कर लो। यह शब्द कहने वाले अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी थे।

ऑनलाइन एजुकेशनः समस्या और समाधान

श्री निवास सिंह

लॉकडाउन की वजह से घर में पूरी तरह कैद बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और उससे जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना मुश्किल होता जा रहा है। अभिभावक भी बच्चों को क्लासेस के दौरान समय दे रहे है तो बाकी वक्त उतना समय नहीं दे पातें हैं, जिससे बच्चों में एकाकीपन बढ़ने लगा था।

कोरोना वायरस और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन ने इंसान या मानव जाति के विकास चक्र की गति को रोक दिया है। आज सभी हर चीज का विकल्प खोज रहे हैं। बच्चों के लिए ये समस्या कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। स्कूल के अलावा तमाम तरह की हॉबी क्लासेस और ट्यूशन और कोचिंग में मशगूल रहने वाले बच्चे लॉकडाउन में सारा दिन घर में रहने को मजबूर हो गए। वर्चुअल गेम्स के दौर में वैसे भी बच्चों का बाहर जाकर खेलना कम हो गया था, लेकिन फिर भी इन क्लासेज के जरिये दोस्तों से मिलना और इंटरैक्ट करना बच्चों की दिनचर्या में शामिल हो गया था। स्कूल की पढ़ाई स्कूल में और होमवर्क ट्यूशन में होने लगे थे। पेरेंट्स के जिम्मे केवल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और असाइनमेंट्स पूरा करवाने की जिम्मेदारी रह गई थी। लेकिन लॉक डाउन ने सबसे ज्यादा बच्चों की दिनचर्या पर प्रभाव डाला।

कहने को तो भारत में अनलॉक-1 शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों के लिए आज भी लॉक डाउन ही चल रहा है। शुरू के कुछ दिन तो परिवार के साथ धमा-चौकड़ी मचाने में बीत गए। ये समय सभी के लिए क्वालिटी टाइम जैसा था, लेकिन फिर जल्द ही स्कूल और कोचिंग क्लास वालों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का प्रावधान शुरू कर दिया। लगभग 3 महीने से स्टूडेंट्स का आधा दिन ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने में ही बीत रहा है। बड़े बच्चे तो इस व्यवस्था में फिर भी ढलने लगे लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस किसी

प्रताड़ना से कम नहीं है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके माता-पिता के लिए भी ये काफी तकलीफदेह है क्योंकि उन्हें पूरे समय बच्चें के साथ क्लास अटेंड करनी पड़ती है ताकि वे बच्चे को क्लास की बातें समझने में मदद कर सकें। ये व्यवस्था सभी के लिए परेशानी वाली है क्योंकि इससे पहले न तो बच्चों को इस तरह की शिक्षा की आदत थी और न ही शिक्षकों को इस तरह पढ़ाने की।

बच्चों को स्वस्थ माहौल देना जरूरी

अनलॉक होने के बावजूद अभी बच्चों की बाहर आवाजाही पर रोक है। ऐसे में अभिभावकों को घर पर ही उन्हें स्वस्थ माहौल देना होगा जिससे बच्चा व्यस्त भी रहे और खुश भी। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे का रूटीन तैयार करें। उन्हें बताएं कि क्लासेस न हों, तब भी उन्हें थोड़ी देर पढ़ना होगा। नीचे दी गई बातें बच्चों का रूटीन सेट करने में मदद कर सकती हैं:

- उनके सुबह उठने और रात को सोने का समय निर्धारित करें
- सुबह उठकर उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पर आपकी मदद करने को कहें। छोटे बच्चे भी टेबल पर प्लेट और ग्लास रखने जैसी मदद आसानी से कर सकते हैं। और नाश्ते के बाद प्लेट वापस सिंक में रख सकते हैं। उन्हें काम मिलेगा तो उन्हें भी जिम्मेदारी का एहसास होगा।
- ब्रेक्फास्ट के बाद ये सुनिश्चित करें की वे ऑनलाइन क्लास शुरू होने से पहले ही नहाकर तैयार हो जाएं। इससे उन्हें अच्छी फीलिंग आएगी। अगर बच्चे छोटे हों, जिनकी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है तो भी उन्हें रेडी करके घर पे ही कुछ पढ़ने का काम देकर एक घंटा स्टडी टेबल पर बिठायें।
- क्लासेज के बाद अगर आप अपने काम में व्यस्त हैं, तो बच्चों को खिलौनों के साथ खेलने के लिए समय निर्धारित कर दें। लेकिन ध्यान रखें की इसमें टीवी वीडियो गेम खेलना शामिल न हो।
- इसके बाद लंच करवाकर उन्हें रेस्ट करने के लिए कहें।
- शाम का समय टीवी और वीडियो गेम्स के लिए रखें।
- देर शाम जब आप भी अपने काम से फ्री हो जाएं तो उनके साथ कुछ गेम्स आप भी खेल सकते हैं। या छत पर वाक करें। इससे एक्सरसाइज भी होगी और इंटरेक्शन का समय भी मिलेगा।
- डिनर वक्त पर करवाकर उन्हें सुला दें। इससे बच्चे व्यस्त रहेंगे और तनाव मुक्त भी।

तनावपूर्ण स्थिति

ये स्थिति सभी के लिए बेहद तनावपूर्ण होने लगी थी। वर्क फ्रॉम होम कर रहे अभिभावकों के लिए बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना मुश्किल होने लगा था। बच्चों को क्लास की पढ़ाई समझने में दिक्कत हो रही थी और टीचर्स को बच्चों को समझाने में तकलीफ हो रही थी। हालांकि इस तनावपूर्ण स्थिति को भांपते हुए कर्नाटक सरकार ने 7वीं क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज पर रोक लगा दी है और शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा कर दी कि केजी-1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। ये निर्णय बच्चों के बढ़ते मानसिक तनाव और अभिभावकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए लिया गया है।

क्या है नया निर्णय

मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन नहीं होंगी और 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक भी रोजाना केवल दो सत्र में क्लासेस होंगी। ये सत्र भी 30-45 मिनट तक के ही होंगे। आदेश के अनुसार प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए व्हाट्सऐप पर होमवर्क जारी कर सकते हैं।

क्यों लेना पड़ा ये निर्णय

लॉकडाउन की वजह से घर में पूरी तरह कैद बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और उससे जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना मुश्किल होता जा रहा था। अभिभावक भी बच्चों को क्लासेस के दौरान समय दे रहे थे तो बाकी वक्त उतना समय नहीं दे पा रहे थे, जिससे बच्चों में एकाकीपन बढ़ने लगा था। बाहर जाना बंद होने की वजह से वे दोस्तों के साथ भी समय नहीं बिता पा रहे थे। इस मुश्किल वक्त में जब बड़ों में ही डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे हों तो बच्चों में तनाव और डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। उधार फीस की चाह में स्कूल लगातार ऑनलाइन क्लास अटेंड करने पर जोर दे रहे थे। जिससे पेरेंट्स को मजबूरी में ये क्लास अटेंड करवानी पड़ रही थी। इसलिए राज्य सरकारों ने हस्तक्षेप करते हुए इन क्लासेज पर प्रतिबन्ध लगवाया है।

ध्यान रखने योग्य बात

मनोविशेषज्ञों के अनुसार बचपन तनावमुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर बचपन में ही बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो फिर न उसकी मेन्टल ग्रोथ ठीक से हो पाती है और न ही फिजिकल ग्रोथ। इसलिए अभिभावकों को अधिक सतर्क रहकर बच्चों को के स्वस्थ बचपन देने का प्रयास करना चाहिए। खुशहाल बचपन एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करता है।

कोरोना का प्रकोप: शिक्षकों के जीवन से खिलवाड़, विभाग बेखबर

निमिषा बाजपेयी

शिक्षा विभाग के अर्न्तगत आनेवाले लगभग सभी कॉलेज अपने शिक्षकों को मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत और अमान्य है। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस ओर सजगता से ध्यान दिया जाए।

कहते हैं हर किसी की जिन्दगी में एक शिक्षक की भूमिका उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे शरीर के लिए अन्न और जल जरूरी है। हमारे शिक्षक न सिर्फ हमें पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी संवारते हैं और हम शुक्रगुजार हैं हमारे शिक्षकों और प्राध्यापकों का कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा है और लगातार अपने छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं।

25 मार्च का वो दिन, जब पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया तब सभी शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए, लाखों छात्रों के मन में न जाने कितने सवालों के सैलाब उमड़ पड़े। अब क्लासेस कैसे होंगे? हमारी परीक्षाएं कैसे होंगी? हम अगले सेमेस्टर में कैसे जायेंगे? और न जाने ऐसे कितने ही सवाल जिनके जवाब हर छात्र के लिए जानना बेहद जरूरी था। तब यही शिक्षक और प्राध्यापक तकनीक की मदद से अपने छात्रों से जुड़ गए और आगाज हुआ ऑनलाइन क्लासेस का। लगभग सभी कॉलेज और शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस और वेबिनार के माध्यम से छात्रों से जुड़ने लगे। पिछले चार महीनों से सभी छात्र घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, ऑनलाइन परीक्षाएं भी गठित की जा रहीं हैं।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार और कॉलेज प्रबंधन से... ... ऐसी विषम परिस्थिति में जब सम्पूर्ण भारत बंद है, सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, केवल डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स और पुलिस कर्मियों को छोड़कर, प्राध्यापकों को कॉलेज बुलाना, वह भी तब जब पहले से कॉलेज में आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं। क्या ये गैरजिम्मेदारी नहीं है? इससे भी बड़ा सवाल: पिछले तीन महीनों से प्राध्यापकों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? और कब तक? सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को कोई मुश्किल न हो, इसलिए निरंतर क्लासेस ली जा रहीं हैं। फिर भी कॉलेज प्रबंधन की तरफ से वहां कार्यरत सभी प्राध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है। इनमें दो कॉलेजों के नाम सामने आए हैं। शारदा यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों से बात करने पर पता

चला कि बस सेवाएं बंद हो जाने के कारण उन्हें पैदल ही यूनिवर्सिटी आना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से बच्चों का मनोबल कमजोर न हो, इसके लिए हर क्लास से पहले 10 मिनट उन्हें कोरोना के बारे में समझाते हैं, ताकि उनका मनोबल कमजोर न पड़े और वे अच्छी तरह से पढाई कर सकें। सिर्फ यह ही नहीं उनका यह भी मानना है कि अभी शारीरिक तौर पर हम भले ही साथ नहीं हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम हमेशा अपने बच्चों के साथ कई तरह की गतिविधियों के जरिये उनका मनोरंजन भी करते हैं। जब हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, तब कॉलेज प्रबंधन हमारी मुश्किलें क्यों नहीं समझ रहे हैं?

जब शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, प्रतिदिन छात्रों के नियमानुसार क्लासेस लिए जा रहे हैं, यहां तक कि वेबिनार के माध्यम से उन्हें अलग तरह से पढ़ाया जा रहा है, फिर भी तीन महीने से उन्हें वेतन क्यों नहीं मिला? कॉलेज प्रबंधन इतनी गैरजिम्मेदार कैसी हो सकती है? हालांकि, ये समझा जा सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तौर पर दिक्कतें आ रहीं हैं, लेकिन प्रबंधन कम से कम 50% वेतन तो प्राध्यापकों और दूसरे कॉलेज कर्मचारियों को दे सकता है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि कॉलेज प्रबंधन ने लगभग सभी छात्रों से उनकी सालाना फीस ले ली है, फिर भी कर्मचारियों को उनके वेतन अदा नहीं किये गए हैं। लॉकडाउन के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाला नहीं जायेगा और न ही उनका वेतन रोका जायेगा। फिर भी शारदा यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों के वेतन पर रोक लगा दी गयी है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर उन्हें आपत्ति है तो नौकरी से इस्तीफा दे दें।

इस तरह से कॉलेज प्रबंधन अपने सभी प्राध्यापकों को मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से कष्ट पहुंचा रहा है, जो की बिल्कुल गलत और अमान्य है। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस ओर सजगता से ध्यान दिया जाए और कॉलेज कर्मचारियों को कम से कम 50% वेतन दिया जाए, जिससे उन्हें भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत हो। इस वैश्विक महामारी के समय हम सब को एक साथ मिलकर यही कोशिश करनी है कि किसी को भी मानसिक तौर पर कष्ट न पहुंचे, किसी के भी मन में तनाव न आये और सभी अपनी जरूरत पूरी कर सकें।

डर और अहंकार के कॉकटेल से उपजी एक खास 'प्रजाति'

मीडिया के एक हिस्से में एक व्यक्ति के नीचे कई लोग काम करते हैं। अधिकांशतः ऊपर वाला व्यक्ति व्यवस्थाओं को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। कई बार निजी स्वार्थ में, तो कई बार 'पूंजीपतियों' और 'सत्ताधारी पार्टी/नेताओं/अधिकारियों' से अपना सिस्टम सेट करने के लिए नीचे के लोगों को अपने तरीके से काम करने के लिए मजबूर करता है। वो उसे लिखने से रोकता है, खबरों का ऐंगल तय करता है, जो 'पत्राकारिता' करने की कोशिश करता है, उसे नौकरी से हटा दिया जाता है या हटाने की साजिश रची जाने लगती है।

मीडियाकर्मियों और पत्रकारों से संपर्क संबंध को लेकर निजी तौर पर मेरा दायरा बहुत छोटा सा है। बहुत अधिक संबंध बनाने का ना ही समय मिलता है और ना ही मीडिया में ऐसा कोई गॉडफादर है, जिसके नाम पर बिना समय दिए संबंध बनाए जा सकें। संस्थानों में क्या हो रहा है, कौन कहां जा रहा है, इससे कोई खास मतलब नहीं रहा। लेकिन अभी हाल में ट्विटर पर एक दिन अचानक टॉप 50 ट्रेंड देख रहा था तो उसमें #MediaMafia दिखा। यह ट्रेंड कुछ रोचक लगा क्योंकि 'मीडिया में माफिया' जैसा मैंने कभी कुछ महसूस नहीं किया था। और वैसे भी मीडिया जैसे जिम्मेदारी भरे काम में माफिया का क्या काम?

खैर, ट्रेंड देखा तो ट्वीट्स भी देखने की इच्छा हुई। ट्वीट्स में कई तरह की बातें थीं। किसी को उसके संस्थान में कथित तौर पर लिखने से रोका जा रहा था, किसी को इस वजह से नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका कोई 'गॉडफादर' नहीं था। कोई किसी संस्थान पर खबरें रोकने का दबाव बनाने का दावा कर रहा था। कोई किसी संस्थान पर नेताओं की पीआर खबरें चलाने का आरोप लगा रहा था। किसी को इस बात का कष्ट था कि मीडिया गरीबों की खबरें नहीं चलाता, तो कोई किसी संस्थान पर समाचारों की जगह पर विचार थोपने का आरोप लगा रहा था। इन ट्वीट्स में कई ऐसे भी थे जो पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान मेरे सीनियर या जूनियर रहे। उनमें से कई से इस बारे में बात की। सभी के अपने तर्क थे। लेकिन इस बीच बीते कुछ दिनों में निजी तौर पर चिंतन करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा।

क्या होते हैं मीडिया माफिया

#MediaMafia को लेकर मेरा मत है कि यह और कुछ नहीं बल्कि छोटे स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों के मन में अपना निजी अहित होने का डर, मिडिल (मैनेजमेंट से मिलकर) स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों का सत्ता से डर और उनमें व्याप्त अहंकार के कॉकटेल से उपजी एक विशिष्ट प्रजाति है। नहीं समझे हैं तो समझिए, किसी एक इलाके में कोई माफिया कब बनता है? जब वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा दिया जाने लगता है। आप किसी गांव में रहते हैं, वहां किसी ने आपके पड़ोसी को दबाने की कोशिश की, वह दब गया, फिर उसका दुस्साहस बढ़ा, वह दूसरे के पास

पहुंचा, उसे दबाया... फिर उसका क्षेत्र बढ़ता गया और वह लोगों को दबाता गया। आगे चलकर वह माफिया बन गया। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं कि वह बहुत दबाया गया हो, उसे व्यवस्था ने बहुत प्रताड़ित किया हो, फिर वह बागी बन गया हो और फिर उसका क्षेत्र बढ़ता जाए। लेकिन इस तरह का अपवाद मीडिया में सामान्य तौर पर नहीं होता।

चाटुकारों को पसंद करते हैं ये लोग

लोगों से हुई बातचीत और अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि मीडिया के एक हिस्से में एक व्यक्ति के नीचे कई लोग काम करते हैं। वह ऊपर वाला व्यक्ति व्यवस्थाओं को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। कई बार निजी स्वार्थ में, तो कई बार 'पूंजीपतियों' और 'सत्ताधारी पार्टी/नेताओं/अधिकारियों' से अपना सिस्टम सेट करने के लिए नीचे के लोगों को अपने तरीके से काम करने के लिए मजबूर करता है। वो उसे लिखने से रोकता है, खबरों का ऐंगल तय करता है, जो 'पत्रकारिता' करने की कोशिश करता है, उसे नौकरी से हटा दिया जाता है या हटाने की साजिश रची जाने लगती है। वो समाचार से ज्यादा विचार पर फोकस करता है। वो कई बार तो इस स्तर तक चला जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी उसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो अपने 'कुकर्मों' का हिसाब नहीं दे पाएगा। वो अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखता है, जो उसके हिसाब से उसके फायदे की बात करें। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें बनाता कौन है? क्या इनपर कोई अंकुश नहीं रहता?

इनके निर्माता 'हम' हैं

आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी, खासकर छोटे संस्थानों में, कि कोई व्यक्ति एक संस्थान से गया तो अपने साथ कई लोगों को लेकर चला गया। या किसी ने कोई नया संस्थान जॉइन किया तो वहां पर अपने कई करीबियों को ले आया। ये सब सामान्य बातें हैं। हो सकता है कि जिन्हें वह लाया हो, उसमें से कई वाकई बेहद प्रतिभावान हों, लेकिन अधिकाशत: ये वही लोग होते हैं जिनसे उस व्यक्ति की 'ट्यूनिंग' अच्छी होती है। नए बच्चों में वो उस संस्थान से निकले लोगों को नौकरी देने की कोशिश करता है, जहां उसने खुद पढ़ाई की हो, या फिर जिस संस्थान में उसके अपने संबंध वाले शिक्षक हों। इस तरह के लोगों को 'हम' बनाते हैं। इस 'हम' में हर स्तर के लोग हैं। चाहे वह कॉपी राइटर हों या संपादक...

भूतकाल की कुंठा, अहंकार बन जाती है

मान लीजिए, एक स्थानीय संपादक या रिपोर्टिंग इंचार्ज अपने से छोटे स्तर के पत्रकार को लगातार दबाने की कोशिश करता है, तो जिसे दबाया जाता है, वह चुप क्यों रहता है, क्यों आवाज नहीं उठाता, क्यों मैनेजमेंट से उसकी शिकायत नहीं करता। बहुत परेशान होने के बाद वह नौकरी छोड़ देता है। नई जगह पर भी वही होता है। 20-25 साल बाद किसी तरह जब वह किसी छोटे-बड़े संस्थान में संपादक बन जाता है तो बीते समय में भरी कुंठा को अपने जूनियरों पर उतारता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उसे नौकरी मिलने के टाइम जैसी समस्याएं आई थीं, वैसी ही दिक्कतें वह दूसरों के लिए खड़ी करता है। उसे लगने लगता है कि संपादक बनने के लिए प्राथमिक आर्हता यही है कि आप 'अहंकारी' हो जाएं। उसका दायित्वबोध शून्य हो जाता है, उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। हालांकि कई बार कोई किसी विशेष प्रकार के 'डर' और 'अहंकार' के कारण भी 'माफियाई' बीज वृक्षाकार रूप लेने लगता है। इस तरह के लोगों में पुराने अनुभवों का कोई रोल नहीं रहता, वे बस अहंकार में अपना काम करते रहते हैं।

इनसे मीडियाकर्मियों का नहीं, देश का नुकसान है

इस तरह के लोगों को जवाब देना सीखिए, ऐसे लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाइए, उन्हें बताइए कि अगर आप संपादक, स्थानीय संपादक, बीट इंचार्ज, सेक्शन इंचार्ज कुछ भी हैं, और आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो उसके ज्ञान और काम को देखकर दीजिए, किसी को नौकरी से निकाल रहे हैं तो भी यही देखिए। निजी संबंधों के आधार पर खासकर इस पेशे में नौकरी देना-निकालना इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि इस पेशे के साथ सैकड़ों-हजारों जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। आम लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, सत्ता के साथ मिलकर, या संबंधों के लिए, या चाटुकारिता के चलते अगर उन आम लोगों की अपेक्षाओं को, उनके सपनों को कुचलने की कोशिश करोगे तो याद रखना वक्त सबका हिसाब लेता है... बाकी निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उनकी खामोशी इस तरह के लोगों को बढ़ावा देती है। ये लोग नहीं हैं, ये सिर्फ एक सोच है जिसमें कुछ लोग फंस गए हैं, इस सोच का खत्म होना मीडिया संस्थानों या पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए जरूरी है... भारत के लिए जरूरी है...

अंतमेंराहतभाईकेएकशेरकीअधूरीपंक्तिकेसाथ अलविदा...
बनकेइंकहादसाबाजारमेंआजाएगा,जोनहींहोगा वोअखबारमेंआजाएगा...

(vishvagaurav.blogspot.comसेसाभार)

कोविड-19: हर मुसीबत जीवन में कुछ न कुछ सिखा कर जाती है

प्रफुल्ल गोस्वामी

आज हम बात कर रहे है देश के राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर चंद्र भूषण शर्मा जी से शिक्षा के क्षेत्रा में आए परिवर्तनों और भविष्य के शिक्षा की नीतियों के बारे में स्वतंत्र स्वरूप के उप सम्पादक **प्रफुल्ल गोस्वामी** द्वारा किये गए कुछ रोचक सवाल-

प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

हमने शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 2017-2018 तक भारत में सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। जिसमे करीब 14 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया, जिसे आने वाले भविष्य में वे छात्रों को भी ऑनलाइन प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित कर सकते हैं। जिसका प्रयोग उन्होंने देश में चल रहे लॉकडाउन के वक्त बहुत बखूबी से किया है। ये NCRT द्वारा किये गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ही सफल हो पाया है।

नो डिटेंशन रूल 2009 के नियम के बारे में आपके क्या विचार है ?

देखिये! अगर मेरी राय इसमें ली जाए तो मैं इस नियम के खिलाफ हूँ, मुझे लगता है कि छात्रों को बिना मेहनत आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसका रास्ता दिखाना बिल्कुल गलत है। हम उन्हें यह शिक्षा दे रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आप चाहें मेहनत करें या ना करें, आपको अगली कक्षा में पहुंचा दिया जायेगा। ऐसे शिक्षण से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि आने वाली पीढ़ी आपके देश का भविष्य बन सकती है जबकि उनकी नींव ही गलत सोच के साथ रखी गयी है और फिर वही सरकार के कुछ लोग शिक्षकों पर आरोप लगाते हैं के वे छात्रों को ठीक से शिक्षित नही कर रहे हैं। अगर छात्रों पर किसी भी प्रकार का कोई बोझ ही नहीं होगा या भय नहीं होगा पास या फेल होने का तो उन्हें शिक्षा हासिल करने में कोई रूचि ही नहीं रह जाएगी और ये चीजें शिक्षकों को भी निराश करती हैं। मैं खुश हूँ के इन नियमों में बदलाव लाए गए हैं और अब से आप खुद परिवर्तन महसूस करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में किसी भी नीति और परिवर्तन का प्रभाव दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, पर उसका परिणाम काफी बेहतर होगा।

छात्र राजनीति पर आपका क्या मत है?

देखिये! पहले तो हमें लगता है कि छात्रों द्वारा राजनीति होनी ही नहीं चाहिए और छात्रों द्वारा की जाने वाली राजनीति उन पर प्रभाव डालने वाले कुछ उपद्रवी तत्व है जो उन्हें गलत प्रशिक्षण के साथ इन चीजों में लाते हैं, जो छात्र समझते हैं ये राजद्रोह है, वे इन चीजों से दूरी बनाए रखते हैं और जो नहीं समझते वे इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। विश्वविद्यालयों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र ऐसी अहिंसा और मतभेदों से दूर रहें और अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा

रूचि ले।

आप IGNOU और JNU के साथ रह चुके है, NCERT का आपका अनुभव बताइए

बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है, NCERT एक बहुत बड़ी संस्था है, जो शिक्षण के लिए कितनी नीतियों को आगे लाने में मदद करती है। जैसे कि मैंने बताया हमने 14,00,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा हमने भारतीय सेना के लिए भी उनके रूचि के विषय जैसे कि इतिहास, मार्शल आर्ट और आर्मी किताबें भी उपलब्ध करवाई है जिनके द्वारा वो आसानी से शिक्षा हासिल कर सकते हैं और यह सबसे बड़ी मुहिम है। विकलांग और नेत्रहीन छात्रों के लिए हमारे द्वारा कई चैनल है जो सांकेतिक भाषा द्वारा उन्हें शिक्षित कर रहे है, मुझे खुशी हैं हम इन नीतियों को लोगो तक पहुंचाने में सफल रहे हैं।

लॉक डाउन में छात्रों के लिए क्या तैयारियाँ की गई है?

हमने ऑनलाइन शिक्षा द्वारा हर एक छात्र और कक्षा के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध करायी हैं। उन्हें बाहर से किताबें या आवश्यक वस्तुएं लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे द्वारा swayamprbha-gov-in ऐसी वेबसाइट उपलब्ध है जो छात्रों को घर बैठे उनकी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करती है, इसके अलावा हमारे द्वारा 32 चैनल चलाए जाते है, जो दूरदर्शन पर उपलब्ध हैं। किन्तु, लॉकडाउन में सरकार द्वारा उन्हें सारे सेट अप बॉक्स पर उपलब्ध करवाए गए हैं, हमारे शिक्षक ऑनलाइन आकर उनकी समस्याओं का निवारण भी कर रहे हैं और हम ये आश्वासन देते है कि लॉकडाउन के बाद भी छात्रों को फिर से सब दोबारा संशोधन करवाया जायेगा, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

आपके अनुसार कोविड-19 का शिक्षण पर क्या असर दिखेगा?

देखिये! हर मुसीबत आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाती है। मैं ये समझता हूँ कि कोविड-19 ने हमारे छात्रों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। हमारे शिक्षकों द्वारा छात्रों को नए तरीके से शिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। हम इसे एक चुनौती की तरह लें और शिक्षण के क्षेत्र में नए परिवर्तन लाने का एक अवसर समझें। हमारा भारत और उसकी युवा पीढ़ी हर चुनौती के लिए पहले भी तैयार थी और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम नई चुनौतियों को आसानी से नए अवसर में तब्दील करेंगे।

आने वाले समय में कोविड-19 के बाद कौन सी नई नीतियाँ तैयार की जाएँगी?

जैसे कि मैने आपको पहले ही बताया कि swayamprb-ha.gov.in द्वारा हम पहले से ही छात्रों तक मटीरियल्स, किताबें और शिक्षकों द्वारा उनके प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं, इसके अलावा हमने 12 नए चैनल प्रक्षेपण करने की नीतियाँ बनाई हैं। 200 नई पुस्तकें, जो E&Pathshala द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगीं। छात्रों को स्वयं अभ्यास करने के लिए शिक्षकों द्वारा जितना भी सहयोग होगा वह सब ऑनलाइन शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। छात्र Skype, Zoom, Google Meet जैसी अलग-अलग अप्लिकेशन्स द्वारा ये सब सुविधाएँ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन के अलावा हमने स्थानीय चैनल प्रदाताओं को भी ये चैनल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

सफलता का मार्ग क्या है?

सफलता की मार्ग सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, मेहनत बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आपको किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसके पीछे जी जान से मेहनत करना जरूरी है, उसका और कोई विकल्प नहीं।

क्या आप छात्रों के माता-पिता के लिए कोई संदेश देना चाहतें हैं?

उनके लिए में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे हमारी योजनाओं में हमें सहयोग करें, अपने बच्चों को आने वाले कल लिए तैयार करें हमारे द्वारा बनाई नीतियों का सही से लाभ लें और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। ताकि, वे आगे चलकर हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य का एक अहम हिस्सा बन सके।

देश के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के चेयरमैन से शिक्षा के विषय में बात करते स्वंतत्र स्वरुप से प्रफुल्ल गोस्वामी

कोरोना की जंग और हारती जिन्दगी

अकील हैदर

हाँ, आज जिन्दगी की गाड़ी थोड़ी धीमी हो गयी है, खुशियों वाली पोटली थोड़ी सी खाली रह गयी है, पर जीवन तो चलने का नाम है, कुछ पाकर तो कुछ खोकर, संयम बनाये रखना ही अपना काम है, हाँ, आज फसलों को कायम रखना है अपनी मजबूरी, क्यूंकि कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए ये दूरी है जरूरी।

एक था 25 मार्च का दिन, जब भारत में सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया और आज लगभग 80 दिन बाद देखिये आप और हम कहाँ है? इस महामारी से लड़ते हुए हमने लगभग 3 महीने बिता दिए और जंग अभी बाकी ही है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार की जा सके, और हम क्या कर रहे हैं? आज भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या साढ़े तीन लाख से ज्यादा हो गयी है। लगभग 9500 लोगों की मौत हो चुकी है इस महामारी से फिर भी हम और आप नहीं समझ पा रहे और बेतहाशा नियमों को ताख पर रख कर बड़े आराम से कोरोना से हाथ मिला रहे हैं।

जी हाँ, ये आप और हम ही हैं जो समझने को तैयार नहीं कि कोरोना किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। कोरोना जात-पात, अमीरी-गरीबी या ऊँच-नीच नहीं देखता। फिर आप क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को संक्रमित कर सकती है। हम सभी जानते है कि अभी पूरा देश आर्थिक दौर से गुजर रहा है, लेकिन अगर आर्थिक परेशानी की वजह से आप कोरोना के संक्रमण में आ गए तो शायद जिन्दगी से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक वायरस ही है। जो सावधानी और एहतियात बरतने से न तो आपके पास आएगा और न ही आपको संक्रमित करेगा। बस अपना 'सुरक्षा कवच' अपने साथ लेकर चले। सुरक्षा कवच है आपका मास्क, सैनिटाइजर की छोटी बोतल और सामाजिक दूरी। यही तो रखना है आपको हमेशा अपने साथ, जब भी घर से बाहर निकलते है तो आप अपना मोबाइल फोन नहीं भूलते, न ही अपना बटुआ भूलते है, उसी तरह से अब इन तीन चीजों को भी नहीं भूलना है।

इस लड़ाई में न जाने कितने योद्धा हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग और कई मदद करने वाले हमारे भाई बंधू हमेशा पूरी सजगता और कर्मठता के साथ दिन रात हमारी और आपकी सेवा में लगे हुए हैं। फिर हम क्यों नहीं इनकी मदद कर रहे हैं, और अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं?

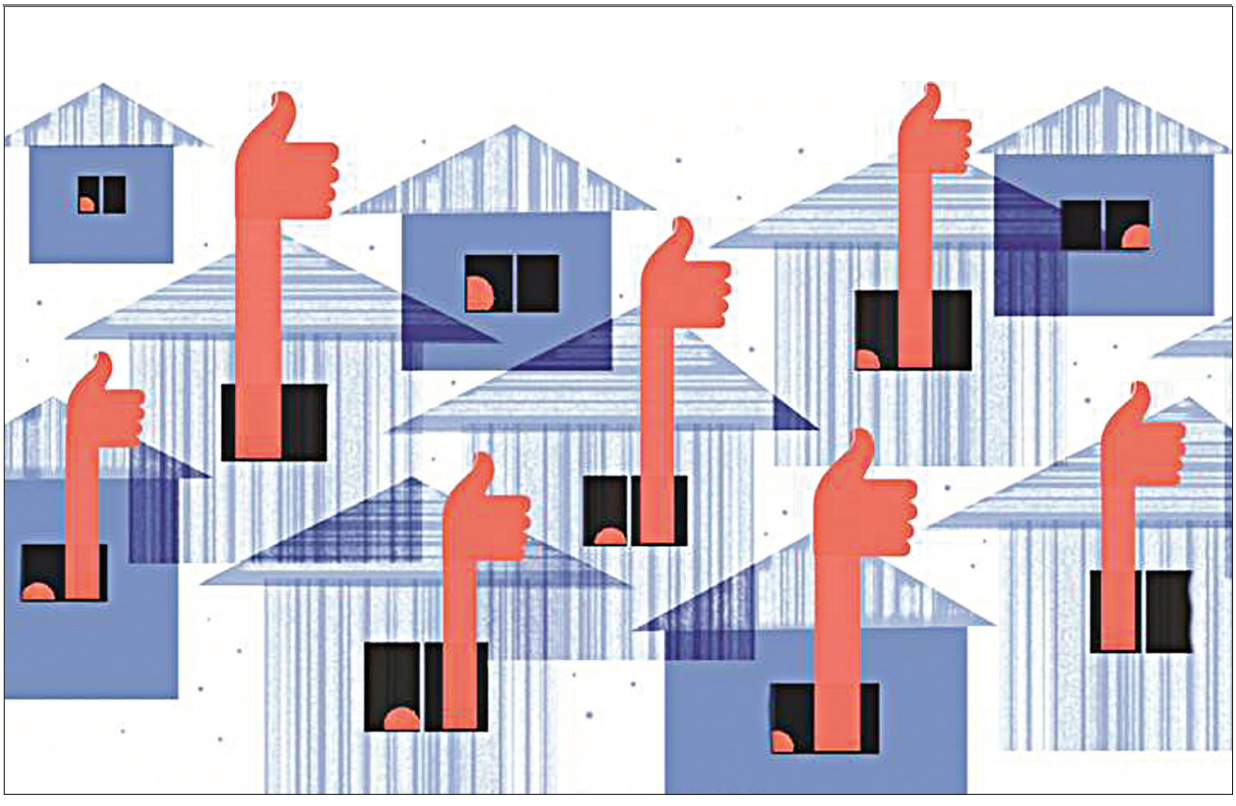

यूँ इस तरह से एक ही दिन में, 11000 से 12000 पॉजिटिव केसेस मिलना इनकी हार नहीं, बल्कि हमारी हार को साफ साफ दर्शा रहा है। हमारे ये योद्धा तो लगे हैं देश सेवा में, और हम लगे है देश को और नीचे की तरफ धकेलने में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है क्योंकि हम सजग नहीं हो रहे हैं। आर्थिक परेशानी का रोना रो कर अपनी और दूसरों की जिन्दगी खराब करने पर आतुर हो गए हैं। लाखों प्रवासी मजदूर आज अपने अपने घरों को जा चुके है। हाँ परिस्थितिवश कुछ लोगों की मौत हो गयी, कुछ भूखे ही सड़कों पर पैदल चल कर जाने लगे।

लेकिनक्याहुआऐसाकीएकपलमेंहीगैरहोगए,
जहांसोचाथाअपनाआशियाँबनाएंगे,
मेहनतसेसींचकरअपनीकुटियासजायेंगे,
आजवहींसेरुखसतहोगए,
बेरंगसीइसजिन्दगीकोलिए,चलपड़ाउनकाकाफिला,
नकुटियासजीऔरनहीरंगोलीरची।

लेकिन हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है, आज सभी मजदूर अपने घरों में है, सुरक्षित हैं, और अब आत्म निर्भर बनने की कोशिश में लग गए हैं। हाँ शुरुआत में दिक्कतें आएँगी, लेकिन परिवार का साथ हो, और अपनों के पास हो, तो शायद ये मुश्किलें भी बीत जाएँगी। हमें बस अब समझना होगा की कोरोना से लड़ने के लिए कोई एक वर्ग ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक एक देशवासी का अब अपना कर्तव्य है की उसे कोरोना की इस जंग को जीतना ही है। अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो हम कोरोना के फैलाव को रोक पाएंगे। जागरूक बनिए और अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइये।

डॉ. सुजीत कुमार
वैज्ञानिक

डॉ सुजीत कुमार को मिला यूएसए में सम्मान

कोविड की त्रासदी से जहां इक तरफ समूचा विश्व परेशान हैं वहीं वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसके कारण फैलाव के तरीके पर तरह तरह के शोध कर रहे हैं। बिहार में पाले बढ़े USA ,Canada के प्रतिष्ठित संस्थानो में अपने कैंसर शोध का लोहा मनवाया चुके डॉ. सुजीत कुमार ने कोरोना कोविड 19 के अभी तक के तथ्यो पर आधारित सर्वेक्षण प्रपत्र लिखा और अमेरिका के जाने माने journel ने उस अर्टिकल को प्रकाशित किया।

भारत हर क्षेत्र में कोरोना को टक्कर दे रहा है चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या कोई। हमारे वैज्ञानिक विश्व को अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।

जैविक खेतीः- स्वास्थ्य के लिए आवश्यक

हेमन्त पटेल

सिक्किम की तर्ज पर देश में जैविक क्रांति को आरम्भ किया जा सकता है। इसके लिए रासायनिक कृषि उत्पादों पर रोक तथा किसानों को प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मोमेंट ने भारत को जैविक खेती अपनाने वाले शीर्ष दस देशों में नौवा स्थान दिया है।

आज से कुछ दशक पूर्व तक के समय में की जाने वाली और आज की खेती में बड़ा बदलाव आया हैं। यह बदलाव कृषि की तकनीक, साधनों एवं रासायनिक उर्वरकों के रूप में समझा जा सकता हैं। हरित क्रांति के नाम पर शुरू किया गया कृषि अभियान इसी का एक हिस्सा था। जैविक खेती (Organic farming) का अर्थ खेती करने की उस विधि से है जिसमें किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक एवं कृत्रिम खाद या कीटनाशक छिडकाव का उपयोग नहीं किया जाता हैं। जैविक खेती में भूमि की उर्वरता को बनाएं रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की बजाय फसल चक्र, हरी खाद और कम्पोस्ट या जीव-जन्तुओं की जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता हैं।

जिस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है कृषि पर बढ़ती निर्भरता व अधिकाधिक उत्पादन के लिए किसानों ने रासायनिक खेती के स्वरूप को अपनाया। इससे पैदावार में बढ़ोतरी तो हुई मगर यह पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। यही वजह है कि 1990 के बाद से जैविक खेती की मांग उत्तरोतर बढ़ती गई।

जैविक खेती का स्वरुप

देश के कई किसान खुद की दवाई खाद और विषरहित जैविक अनाज की मानसिकता के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर कृषि उत्पादन कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों में मौजूद रासायनिक तत्व मानव शरीर के लिए घातक होते हैं। शोध बताते है कि इन तत्वों से मनुष्य में किडनी रोग, हृदय रोग, दमा, कैंसर, सिरदर्द जैसे रोग हो सकते है, महंगे होते रासायनिक कीटनाशकों को खरीदना किसानो को भारी पड़ने लगा हैं। इस कारण अब उनका रुझान भी रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर बढ़ा हैं।

इस पद्धति में खेती में बोई जाने वाली फसलों पर कृत्रिम रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता हैं। जैविक खाद, गोमूत्र, पुरानी छाछ, नीम व अन्य पत्तियों से तैयार किये गये प्राकृतिक कीटनाशक फसलों पर छिडके जाते हैं इससे जैविक उत्पाद भी पौष्टिक व ज्यादा स्वादिष्ट होता हैं।

जैविक खेती क्यों जरूरी :

कृषकों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने का मूल उद्देश्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाने तथा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक पदार्थों के दुष्प्रभाव को कम करना। ऐसे कीटनाशक तैयार किये जाए जो मृदा में अघुलनशील हो तथा खरपतवार व हानिकारक जीवाणुओं को मिटाने में कारगर हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाइट्रोजन से जैविक खाद तथा कार्बनिक पदार्थों को पुनः उपयोगी बनाया जाता हैं।

जैविक कृषि किसान के लिए सबसे उपयुक्त मानी गयी है जिसके चलते वह पालतू जानवरों की देखभाल कर सकेगा, उनके जीवन स्तर तथा रखरखाव में मदद मिलेगी। जैविक कृषि का एक अहम लक्ष्य पर्यावरण पर रासायनिक प्रभावों को कम करना तथा प्रकृति के साथ बिना छेड़छाड़ किये सहजीवी बनकर इसकी सुरक्षा करना हैं।

आर्गेनिक खेती के फायदे :

आज जहाँ रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशको की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि किसान ऋणग्रस्त होकर खेत में बुवाई करता हैं। ऐसे में यदि वह इस रासायनिक खाद के साथ पर पशुओं,

पेड़ों पौधों के अवशेषों से निर्मित जैविक खाद का उपयोग करे तो कृषि की लागत भी कम आएगी और किसान का जीवन भी खुशहाल हो सकेगा।

निरंतर केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है साथ ही भूमि के जल स्तर में भी कटौती होती जाती हैं। जैविक खाद के प्रयोग से बम्फर उत्पादन भी होगा, भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ेगी तथा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता हैं। जैविक खेती पूरी तरह पर्यावरण मित्र होती हैं।

जैविक खेती का प्रत्यक्ष एवं तत्कालीन लाभ कृषक को दो तरह से मिलता हैं। पहला उनके स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को तथा दूसरा किसान की भूमि को जैविक खेती के लिए प्राकृतिक खाद का उपयोग करने से भूमि का उपजाऊपन तो बढ़ता ही है साथ ही सिंचाई चक्र की अवधि भी बढ़ जाती हैं।

भारतीय कृषि में जैविक खेती की आवश्यकता व महत्व :

आजादी के समय तक भारत में अन्न की व्यापक कमी का दौर था। उस समय तक प्राचीन परम्परागत कृषि का स्वरूप चलन था, सरकारी नीतियों के चलते न तो किसान को कोई मदद मिलती थी ना ही उनका कोई मददगार था। ऐसे में जब 60 के दशक में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ तो किसान उत्तरोतर लाभ के लिए अपनी उपजाऊ जमीन में भी रसायनों के प्रयोग से अधिक पैदावार करने लगे। जहाँ एक बीघा में किसान एक क्विंटल उर्वरक डालता था अब वह तीन क्विंटल डालकर अधिक पैदावार तो करने लगा मगर यह लाभ तात्कालिक ही था, कालान्तर में उसकी भूमि बंजर में बदलने लगी।

भारत ही नहीं समूचे संसार में आज तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक गम्भीर समस्या बन चुकी हैं। अधिक जनआबादी के भोजन के लिए अधिक अन्न, फल, सब्जियां उत्पादन के लिए किसान अपने खेतों में नाना प्रकार के रसायन, कृत्रिम खाद और जहरीले कीट नाशकों का उपयोग करते हैं। इससे प्रकृति के संतुलित सघटन जैविक व अजैविक पदार्थों के पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता हैं। तय सीमा से अधिक मात्रा में रसायनों के उपयोग से भूमि की उर्वरा क्षमता समाप्त होकर बंजर का रूप ले लेती हैं। खेतों में प्रयुक्त रसायनों से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है इसका सीधा सम्बन्ध मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हैं। पुराने जमाने में खेती का जो स्वरूप प्रचलन में था उसमें मनुष्य के स्वास्थ्य तथा प्रकृति के वातावरण का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। परम्परागत जैविक खेती से जैविक व अजैविक घटकों का सामजस्य बना रहा, यही कारण है उस समय जल, वायु या मृदा प्रदूषण की समस्या ने जन्म नहीं लिया। हमारा भारत गायों का देश था हर घर में गाय का पालन किया जाता था। गाय और बैल किसान के मित्र समझे जाते थे। मगर आज यांत्रिक कृषि ने इन्हें मनुष्य से दूरी बना दिया हैं। परिणामस्वरूप खेतों में जैविक खाद के स्थान पर रासायनिक खाद का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा।

भारतीय किसान अब फिर से जैविक कृषि की ओर उन्मुख हुए है। भारत में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में 2001-02 में प्रत्येक ब्लॉक पर ऑर्गेनिक खेती को आरम्भ किया गया तथा उन गाँवों को जैविक गाँव कहा गया। इस अभियान की शुरुआत के प्रथम वर्ष में ही 300 से अधिक गाँवों ने रासायनिक खेती का त्याग कर जैविक कृषि को चुना। अगले ही साल ब्लोक स्तर पर दो दो गाँवों को प्रेरित किया गया। तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात जैविक गाँव के आन्दोलन को 2006 में फिर से आरम्भ किया और इस बार ब्लोक स्तर पर 5-5 गाँव चुने गये इस प्रकार तीन हजार गाँवों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जैविक खेती को अपनाया।

शरीर हेतु स्वास्थ्य लाभ

यदि जैविक कृषि के लिए एक स्वस्थ कृषि पद्धति जन्म लेती है अथवा नयें युग व साधनों के अनुरूप अच्छी कृषि व्यवस्था का जन्म होता है तो देश व दुनियां की पैदावार तथा स्वास्थ्य सूचकांक में बदलाव अपेक्षित हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले शोध कर्ताओं का विश्वास है कि जैविक कृषि के सम्बन्ध में असीम सम्भावनाएं हैं। पश्चिम के देशों के लिए यह एक नवीन व्यवस्था है जिसमें किसान रुचिकर हैं। मगर भारत के विषय में एक लुप्त पुरातन व्यवस्था को पुनर्जीवित करना हैं। सिक्किम वर्ष 2016 में देश का प्रथम जैविक राज्य बना था। यहाँ के कृषकों ने 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक प्रथाओं एवं जैविक कृषि पद्धतियों से पैदावार प्राप्त की। जिसमें किसी प्रकार के रसायन का खाद, कीटनाशक या अन्य रूप में उपयोग नहीं किया गया था।

सिक्किम की तर्ज पर देश में जैविक क्रांति को आरम्भ किया जा सकता हैं इसके लिए रासायनिक कृषि उत्पादों व रोक तथा किसानों को प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देने की आवश्यकता हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मोमेंट ने भारत को जैविक खेती अपनाने वाले शीर्ष दस देशों में नौवा स्थान दिया हैं। हमारे देश में अबाधित रसायनिक खेती के पीछे का कारण ज्ञान का अभाव हैं। एक आम किसान को इनके हानिकारक प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी नहीं हैं। वह यह भी नहीं जानता कि इस कार्य में वह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा हैं।

आज से 18 साल पहले जैविक खेती का भारत में सफल प्रयोग हुआ, एक किसान आन्दोलन के रूप में मध्यप्रदेश में इसे पूर्ण सफलता मिली। भारत के साथ साथ पश्चिम के देशों को भी इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, मगर इस अभियान से जुड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या सम्पूर्ण देश में जैविक खेती को पुनर्जन्म दिया जा सकता हैं। हमारे देश में कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ भूमि है, कुल भू-क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर कृषि की जाती हैं। देश की 58 प्रतिशत जनसंख्या का रोजगार क्षेत्र भी कृषि हैं।

यही कारण है की सभी देशो की सरकारें आज जैविक खेती को लेकर अति संवेदनशील हो गई है तथा केंद्र हो या राज्य स्तर या फिर जिला स्तर सभी जगह जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग तत्पर रूप से कार्य कर रहे है और सरकार द्वारा जैविक खेती के उत्पादों को प्रमाणित करने हेतु सरल एवं सुविधा जनक योजना बनाई है ताकि जैविक खेती करने वाले किसानो को अपने उत्पाद को विक्रय करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। द

भविष्य में जैविक खेती मानव जीवन हेतु अनिवार्य हो जाएगी

कैसे करें आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट

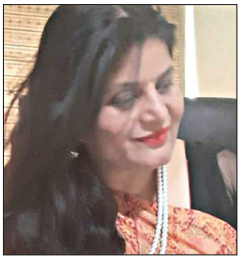

दिव्या दीक्षित

आधार पर सिर्फ अड्रेस ही ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। नाम या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको एनरॉलमेंट/अपडेट सेंटर विजिट करना होगा।

आधार कार्ड अब भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड पर 12 अंको का एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। आधार कार्ड बनाने के लिए किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा और डेमोग्राफिक डेटा लिया जाता है। अक्सर लोगों को इसे अपडेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां हम आपको बतायेंगे कि आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए।

अड्रेस अपडेट करने के लिए क्या करें?

अगर आपने हाल ही में अपना शहर या घर बदला है तो आप आधार पर ऑनलाइन अपना अड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

1. सबसे पहले आधार की वेबसाइट पर लॉगिन करें
2. अपना नया अड्रेस डालें
3. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
4. रिक्वेस्ट सबमिट करें
5. अपना URN नंबर (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) सेव करें।

अड्रेस प्रूफ न हो तो क्या करें?

अगर आपके पास वैलिड अड्रेस प्रूफ नहीं है तो UIDAI के अड्रेस वेलिडेशन लेटर के जरिए अपना अड्रेस ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

1. सबसे पहले आधार की वेबसाइट पर लॉगिन करें
2. लेटर पर लिखे सीक्रेट कोड एंटर करें
3. अड्रेस को प्रीव्यू करें
4. अपना URN नंबर (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) सेव करें।

आधार पर कैसे अपडेट करें नाम और मोबाइल नंबर ?

आधार पर सिर्फ अड्रेस ही ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। नाम या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको एनरॉलमेंट/अपडेट सेंटर विजिट करना होगा। सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही आप नाम या मोबाइल नंबर अपेडट कर सकते हैं। अपने आस-पास एनरोलमेंट सेंटर की जानकारी आप uidai-gov-in पर 'लोकेट एनरॉलमेंट सेंटर' पर क्लिक करके ले सकते हैं।

नाम बदलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आधार कार्ड पर नाम बदलने के लिए जरूरी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है। नाम अपडेट करने के लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है। सेंटर पर इन्हें स्कैन करके वापस कर दिया जाता है। आधार पर ऑनलाइन अपडेट के लिए आपको कोई शुल्क नहीं चुकाना होता जबकि सेंटर पर जाकर आधार कार्ड की जानकारी में बदलाव करने के लिए आपको 25 रुपये शुल्क देना पड़ता है।

हैवानियत की हदें पार: अब करना है मर्दानगी पर वार

दीपिका

कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, अपनी हवस को पूरा करने के लिए, ये सोचने में भी हमें समय लगता है, और उस इंसान की दरिंदगी सामने आने में बिलकुल भी समय नहीं लगता।

कहने को तो हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आधुनिक ख्याल, नयी सोच और ना जाने कितने ही आधुनिकरण से हम घिरे हुए हैं। लेकिन आज भी हमारा समाज और इसकी छोटी मानसिकता न तो बदली है और न ही बदलेगी। आज भी औरतों को एक सामान की तरह ये मर्द और हमारा समाज समझता है। जैसे किसी चीज को उपयोग करो और जब मन भर जाये तो उसे या तो फेंक दो या फिर बेच कर नया खरीद लो। यही इज्जत है एक औरत की हमारे आज के तथाकथित समाज में, लेकिन अब बस, मर्दों की हैवानियत की हदें अब पार हो चुकी हैं। उन्हें समझना होगा की औरतें कोई इस्तेमाल की वस्तु नहीं है, न ही कमजोर है।

एलेक्ट्रोम कम्युनिकेशन कंपनी की शुरुआत

अंकिता (24 वर्ष) (काल्पनिक नाम) ने सुभारती यूनिवर्सिटी से अपनी बी.टेक की पढाई पूरी कर, इक्लेक्ट्रोम कम्युनिकेशन (नॉएडा) में बतौर एच.आर. के पोस्ट पर अगस्त, 2018 में काम करना शुरू किया। कंपनी के मालिक मिथिलेश झा ने शुरू से अंकिता को हर काम की छूट दे रखी थी। दरअसल, मिथिलेश झा ने एक नयी कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी की सबसे पहली कर्मचारी अंकिता ही थी। अंकिता के कंपनी में आने के बाद, उन्होंने ही एक ऑफिस बॉय को रखा। साथ ही तकनीकी टीम भी गठित की। इसके साथ ही अंकिता ने अवनि (काल्पनिक) को पी.आर. के पद पर नियुक्त किया। इस तरह से कंपनी में कई लोग जुड़ गए और कंपनी सुचारु रूप से काम करने लगी।

कंपनी के मालिक मिथिलेश झा की गलत नीयत

अंकिता के अनुसार, 'रार रात भर काम करवाना, सारे कर्मचारियों के जाने के बाद भी मुझे रोके रखना, जान बुझ कर लेट तक रोकना, काम से परे कुछ अजीबो गरीब बातें करना, इनकी आदत बनते जा रही थी। शुरू-शुरू में मुझे लगा की शायद मेरे लिए ये एक नया जॉब है, मैं इसमें ढलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये इनकी आदत बन गयी। झूठ बोलकर हमें कॉफी के लिए आमंत्रित करना, इधर-उधर की बातें करना, बिना वजह छूना, ये सब मुझे बहुत असुविधाजनक लगने लगा था. 12 बजे रात तक ऑफिस में रोक कर रखना, और फिर सुबह जल्दी बुलाना, मैं मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो रही थी और सबसे बड़ी बात की जब आप किसी के साथ काम

कर रहे हो और आप को अंदर से ये महसूस हो की वो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, तब काम करना और भी मुश्किल हो जाता है।'

अपनी गन्दी सोच को अंजाम देने की मिथिलेश झा की साजिश

कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, अपनी हवस को पूरा करने के लिए, ये सोचने में भी हमें समय लगता है, और उस इंसान की दरिंदगी सामने आने में बिलकुल भी समय नहीं लगता। अंकिता के अनुसार, '22 अक्टूबर को मिथिलेश सर ने कहा की ऑफिस मीटिंग के लिए बेंगलुरु जाना है, बहुत जरूरी लोगों से मिलना है, कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुझसे कहा गया की अच्छे से प्रेजेंटेशन और सारी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लूँ। मैंने सारी तैयारी कर ली। मुझे लगा कंपनी की मीटिंग है तो सभी जायेंगे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मुझे पता चला की ऑफिस का और कोई कर्मचारी उनके साथ नहीं था, सिर्फ मैं और खुद मिथिलेश झा। मुझे वही थोड़ा खटका और मैंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और कहा कि अवनि (पी.आर.) को भी मैंने बोला था लेकिन, ऐन मौके पर उसकी तबियत खराब हो गयी, मुझे मजबूरी में उनके साथ बेंगलुरु जाना पड़ा। फ्लाइट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं की, मुझे लगा बंदा समझ गया और शायद अब कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा।'

'लगभग रात के 12 बजे जैसे ही हम बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे, हमने कैब बुक की, और ले मेरीडियन होटल, जहाँ हमारी बुकिंग थी, वहां के लिए निकल गए। 2 बजे के आस पास हम दोनों होटल पहुँचे और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गयी, जब मुझे पता चला की इसने सिर्फ एक ही रूम बुक की है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी उनके साथ एक ही रूम में रहने की, हम एक आधिकारिक मीटिंग के लिए गए थे, इसलिए मुझे लगता है की हमें वो प्रोटोकॉल बनाये रखना चाहिए था। पूरे होटल में और कोई रूम खाली भी नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त को, जो बेंगलुरु में ही रहता है, वही से फोन किया और कहा की मुझे आकर ले जाये। तब तक मिथिलेश सर ने कहा की रूम में चलते और कुछ खा लेते हैं, फिर जब मेरा दोस्त आये, मैं उसके साथ चली जाऊं। रात के 3 बजे हम लोग रूम में गए और उसने खाने का आर्डर किया। फिर रूम को लॉक कर दिया, और मेरा फोन मेरे हाथों से छीन लिया, और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मुझे जबरदस्ती पकड़ कर मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गयी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था की क्या करूँ, बहुत हाथ पैर चलाये, उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से उसे जोर से अपने पैरों से मारा, और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब तक मेरा दोस्त नीचे आ गया था, और मुझे फोन कर रहा था, लेकिन फोन मिथिलेश के पास होने की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पायी। काफी देर इंतजार के बाद मेरा दोस्त चला गया।'

'जब मिथिलेश को लगा की मैं मानने वाली नहीं, और बेतहाशा चिल्लाये जा रही थी, उसने अपने आप को सँभालने की कोशिश की, और फिर मुझसे कहा की वो मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए मुझे मनाने की झूठी कोशिश करने लगा। लेकिन मैं उसके झांसे में नहीं आयी। मैंने किसी तरह फोन उससे छीना और कहा की दरवाजा खोल दे नहीं तो 100 डायल कर मैं पुलिस को बुला लूँगी। डर से उसने दरवाजा खोल दिया और अपनी गलती छिपाने के लिए मेरे पैरों पर गिर कर मुझसे माफी मांगने लगा। बार बार मुझे सॉरी कहने लगा। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी, और अपना सामान लेकर, वहां से अपनी एक दोस्त के घर चली गयी। कल मैंने अपने सर को सारी बात बताई, जिन्होंने मुझे वहां नौकरी पर रखवाया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया की हम कड़ी कार्यवाही करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दिल्ली वापिस आ जाना चाहिए। अगले

ही दिन मैंने फ्लाइट लिया और दिल्ली वापिस आ गयी। एयरपोर्ट पर मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने और मैं घर आ गयी।'

यहां पर मुझसे ये गलती हो गयी की मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा की इतना सब होने के बाद मेरे पिता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए डर से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कल होकर मैं ऑफिस गयी, और अपने सर को भी बुलाया जिन्होंने मुझे वहाँ नौकरी पर रखवाया था, और वहाँ पहुँचने के बाद, हद तो तब हो गयी जब मिथिलेश अपनी बात से पलट गया। उन्होंने साफ इंकार कर दिया, की उन्होंने ऐसा कुछ किया है, और उलटा सारा इलजाम मेरे ऊपर डाल दिया, ये कहते हुए की मैंने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। मैंने आव देखा न ताव, और एक जोर का तमाचा पूरे ऑफिस के सामने मिथिलेश को दे मारा। मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी। मैंने ये तक कहा की होटल ले मेरीडियन के वीडियो फुटेज भी चेक किये जा सकते हैं, जब मैं रात के 3 बजे होटल से निकल कर अपनी दोस्त के घर जा रही थी, और मैंने वहीं से सर को अपनी लोकेशन भी भेज दी थी। इतना कहने पर मिथिलेश तुरंत से पलट गया और फिर उसने मुझसे माफी मांगनी शुरू कर दी। अब पानी सर से ऊपर हो गया। मैंने सोचा की ऐसे लोगों को कानून सजा दे, तो शायद अच्छे से समझ आये। जैसे ही मैंने पुलिस में शिकायत करने की बात कही, इसने मुझे पैसों का लालच देना शुरू कर दिया। कहा जितने चाहिए ले लो और बात को रफा दफा करो। मुझे फिर गुस्सा आया और मैंने फिर से जोर का एक तमाचा उसके गालों पर दे मारा और वहाँ से निकल गयी।

क्यों और कब तक लड़कियों को सहना होगा?

अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ, वो हमारे आपके लिए शायद एक आम बात होगी क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है। 2018 में यौनशोषण के खिलाफ 35000 से ज्यादा मामले दर्ज किये गए है। मतलब लड़की नहीं, जैसे कोई चीज हो, इस्तेमाल करो, मजे लो, फिर फेंक दो। आज हमारे समाज को ये समझना होगा की अब बस, बहुत हो गया, हम कोई राह चलती वस्तु नहीं है, जिसे जब चाहा छू लिया, हम कोई पौधे में लगे फूल नहीं है, जिसे जब मन चाहा तोड़ कर मसल कर उसकी खुशबू लेनी चाही। कई लड़कियां समाज के डर से आगे बढ़ कर बोल नहीं पाती तो कई परिवार की इज्जत के लिए चुप रह जाती हैं। कई तो मानसिक तौर पर प्रताड़ित होती है और फिर आत्महत्या तक कर लेती हैं। यही नहीं, कई लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे या तो जिंदा जला दिया जाता है या फिर मार कर नदी में बहा दिया जाता है, और ये कोई नयी बात नहीं है, हर दिन ये होता आ रहा है और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बर्बरता की हदें पार कर देगा।

संवैधानिक रूप से यौन उत्पीड़न

हम एक लोकतान्त्रिक देश में रहते हैं। एक ऐसा देश जिसे अपनी वृहत संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। जहाँ औरतों को माँ के रूप में पूजा जाता है। ये सब अब सिर्फ किताबी बातें लगती हैं। जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज लड़कियाँ अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। संविधान में अनेकों कानून बने हैं, यौन उत्पीड़न को लेकर कई तरह की धाराएं है। IPC सेक्शन 354। , 354B , 354C , 354D इन सब में महिलाओं के साथ बलात्कार, और यौन उत्पीड़न को लेकर कानून बने हैं। हम मानते हैं, कानून के अनुसार हर व्यक्ति को सजा होगी। लेकिन उस लड़की का क्या, जिसे जिन्दगी भर की सजा मिल गयी है। कोई सोच भी नहीं सकता किस दर्द से एक लड़की गुजरती है, जब उसके साथ बलात्कार अथवा यौन शोषण किया जाता है।

कथित आरोपी मिथिलेश झा

बात अब हमारे अस्तित्व की है। हम कहीं भी रहे, एक डर मन में समाये रहता है कि कोई हमें घूर तो नहीं रहा। कोई हमारे कपड़े पर नजर तो नहीं डाले है, कहीं हमारा पैर या शरीर का कोई अंग दिख तो नहीं रहा। हम अपने मन मुताबिक कपडे नहीं पहन सकते। रात में अकेले आ जा नहीं सकते। हमेशा यही डर रहता है की कई कुत्ते बाहर सड़क पर बैठे होंगे, और हमारी राह तक रहे होंगे, की हम कब आये और वो हमें अपनी हवस का शिकार बनाये। अब लड़कियों को समझना होगा, हमें न तो निर्भया बनना है न ही उन्नाओ रेप केस की तरह जल कर मरना है। हमे बस अपनी आजादी चाहिए। आजादी उस डर से, जो रात में अकेले आने जाने में है। आजादी उस सोच से, कि हम इस्तेमाल की कोई वस्तु हैं, आजादी उन गन्दी नजरों से जो हमेशा हमें घूरती रहती हैं, आजादी उन घिनौने शब्दों से जिससे हमें बुलाया जाता है। हम न तो माल हैं, न पटाखा, न ही तीखी मिर्ची, हम एक आम इंसान है, जिसे जीने का उतना ही हक है जितना समाज में रह रहे दूसरे लोगों को।

हम पर पर्दा डालने से पहले अपनी आँखों पार पड़े परदे को हटाने की जरूरत आन पड़ी है। हैवानियत कि हदें पर वालों की मर्दानगी पार अब वार करना है। ऐसे कितने ही मिथिलेश झा समाज में घूम रहे हैं, अब इन्हे इनकी औकात दिखानी है। समय के साथ सोच भी बदलने की जरुरत अब आन पड़ी है। अपनी बेटियों को सिखाना है कि कोई भी कहीं भी आपको छू नहीं सकता, अपनी सुरक्षा उन्हें खुद करनी है। आने वाली पीढ़ी को इतना मजबूत बनाना है कि फिर से कोई निर्भया न बने जिनके माँ बाप को सात साल कि मशक्कत के बाद न्याय मिला। अब केस फाइल नहीं करना है, बल्कि खुद में तैयार रहना है, हम खुद सजा देंगे।

इतिहास के नाम पर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ क्यों ?

पूर्ति सिंह

भारत की पहचान भारत की प्राचीनतम सभ्यता का एक प्रतिबिम्ब माना जाता है। वही सभ्यता जिसे आज पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार बैठा है और ऐसा हो भी क्यों न? आखिरकार भारत की संस्कृति और सभ्यता ने किसी मनुष्य का नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर जन्म लेकर उसे जीवन देने वाले मनुष्यता के भाव का निर्माण करती है। लेकिन, आज के इस बदलते दौर में कहीं न कहीं हमारी संस्कृति हमारे मनोमस्तिष्क से मिलो दूर जा चुकी है, जिसके चलते हम अपनी भारतीयता से जुड़ी हुई वास्तविक पहचान को खोते जा रहे हैं। जिसका पूरा लाभ भारत पर हुकूमत करने की चाह रखने वाले नेताओं को बराबर मिलता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वे हमें हमारी पहचान नहीं बल्कि मुगलों की पहचान कराने से भी नहीं चूक रहे हैं।

संस्कार, शुद्धि, समर्पण, सद्भावना, प्रेम, सौहार्द, मानसिक विकास, सौन्दर्य तथा सभ्यता इन सभी शब्दों का वास्तविक अर्थ है भारतीय संस्कृति। ये सभी शब्द संस्कृति संस्कार आदि शब्दों से परिणत हो जाते हैं। हमारी संस्कृति अति प्राचीन व भव्य होने के साथ देवताओं की भूमि भी है। इसे साबित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत का प्राचीन इतिहास रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि हमारी संस्कृति के परिणामस्वरूप सामने आते रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति अथवा उसके इतिहास से होती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहासरूपी विशाल वृक्ष को कई आक्रांताओं द्वारा मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया लेकिन अनेंकों प्रयासों के बाद भी इसकी जड़ें पहले से और अधिक मजबूती हो गईं। आज यह जड़ें अपने स्थान पर मौजूद हैं। वर्षों पहले जब कभी भारतीय संस्कृति का जिक्र होता था तो भारतीय इतिहास को प्रमुखता के साथ जोड़ा जाता था क्योंकि उस समय तक भारतीय संस्कृति की पहचान उसके शौर्य से भरे इतिहास से होती थी और इसी इतिहास की पहचान मानवता व प्रेम से भरी संस्कृति से ही रही थी लेकिन समय के साथ अनेंकों बदलाव भी हुए। वर्तमान समय ने भारत की संस्कृति और उसके इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया है। आज के समय में भारतीय संस्कृति का अर्थ मात्र हिन्दुत्व और हिन्दु रिति-रिवाज हो गया है। इसके अलावा भारत की संस्कृति को सिर्फ अकबर, हुमांयु, शाहजहां की इमारतों को जोड़ा जाता रहा है। क्या यह उचित है और क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है?

पूर्व से ही भारत की संस्कृति और उसकी परम्परा को भिन्न-भिन्न तरीकों से मिटाने का पूरा प्रयत्न किया गया। जैसे- कभी मन्दिरों को नष्ट करने के नाम पर तो कभी भारतीय सभ्यता में आधुनिकता लाने के नाम पर। अनेंकों प्रयासों के बाद यहां की सनातनीय परम्परा का एक अंश भी कोई मिटा न सका। भारत की सनातनीय परम्परा न सिर्फ यहां कि सभ्यता का आईना है बल्कि भारत के भविष्यदर्शन का उदाहरण है। भारत में कई ऐसे पूर्वकालीन भव्य मन्दिर हैं, जिनसे सुसज्जित दीवारों और उनके स्तम्भों पर उकेरी गई उसकी कला को देखकर ऐसा प्रतीत

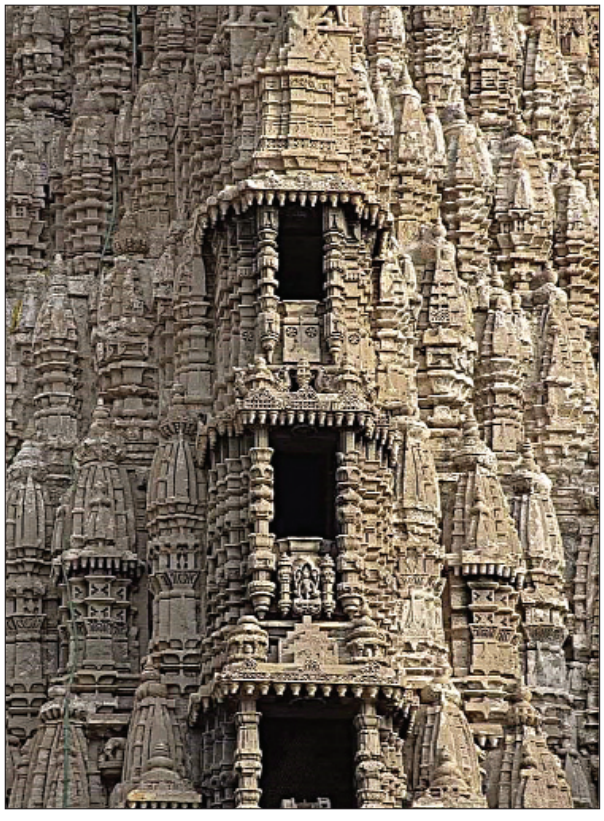

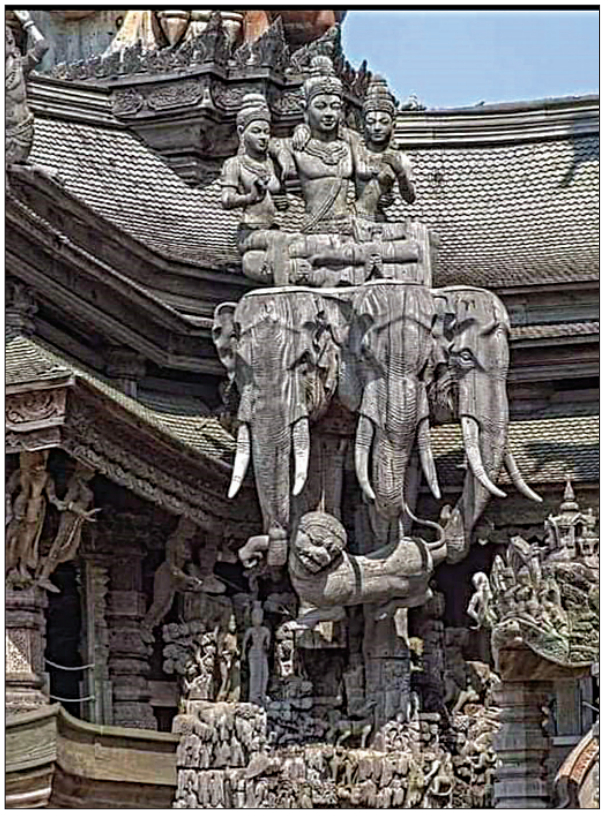

होता है जैसे उस काल के लोगों को यह ज्ञात होता था कि भारत और उसकी सनातनीय सभ्यता का भविष्य कैसा होने वाला है। 11वीं सदी के आसपास गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालीताणा मन्दिर की दीवारों पर बनी वास्तुकला दिखने में कुछ ऐसी है जैसे- वर्तमान समय की स्थिति को अथवा वर्तमान समय में मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आधुनिक उपकरणों को किसी कलाकार ने दर्शकों के लिए दीवारों पर स्थापित कर दिया हो। मन्दिर की दीवारों पर कहीं महिला द्वारा हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की वास्तुकला उकेरी गई है तो कहीं, अन्य आधुनिक उपकरणों को मनुष्य के हाथ में दिखाया गया है। अब विचार करने की बात यह है कि भारतीय संस्कृति को व्यर्थ समझने वाले इस पुरातन और भारतीय सभ्यता से जुड़े वास्तविक सत्य को किस प्रकार स्वीकार करेंगे? 21वीं शताब्दी में भले ही हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे निकल गए हों लेकिन 11वीं शताब्दी में उकेरी गईं कला और उस कला के माध्यम से बनीं इन मूर्तियों में दिखाए जा रहे भविष्यदर्शन के मुकाबले आज भी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। मुझे समझ नहीं आता कि अनिष्ठकारियों ने भारत में ऐसा कौन-सा इतिहास रचा, जिससे हमारे राष्ट्र की पहचान हो सके? बाल्यावस्था से युवावस्था तक पढ़ाई जा रही पुस्तकों में एक ही विषय को बार- बार पढ़ाया गया कि अकबर, बाबर, महमूद गजनवी कौन थे? इन्होंने कितने वर्ष भारत पर राज किया? इतना ही नहीं यहां कि सत्ता पर काबिज राजनेताओं ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए आक्रान्ताओं द्वारा छोड़ी गए ताजमहल, लालकिला, कुतुबमीनार जैसी निशानियों को भारत में एतिहासिक पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया। क्या यह मानना उचित नहीं होगा कि इन सत्तालोभी

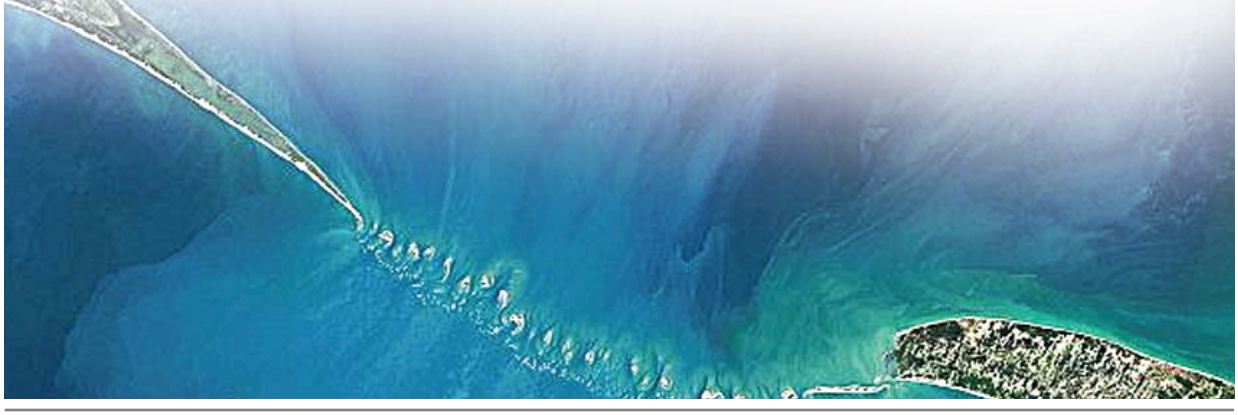

कोणार्क मंदिर का सूर्य चक्र

राजनेताओं द्वारा यह कुक्रत्य सिर्फ भारत कि संस्कृति और सभ्यता को मिटाने के लिए किया गया हो? देश- विदेश से आने वाले लोग इन चन्द इमारतों को भारत का इतिहास समझते रहे हैं, जबकि इससे कई बेहतर हमारी भारतीय संस्कृति और उससे जुड़ा भारत का इतिहास रहा है। जिसकी एक झलक मात्र ही दर्शकों को असमंजस की स्थिति में डाल देती है। आज की पीढ़ी उन सत्तालोभियों से प्रश्न करती है कि जब हमारी एतिहासिक संस्कृति हमारे लिए अन्य से अधिक महत्वपूर्ण और अत्यधिक विशाल थी तो किस कारण से उसे हम भारतीयों से अनभिज्ञ रखा गया? आखिर हमारी पुस्तकों में रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धार्मिक ग्रन्थों से जुड़ा हुआ ज्ञान क्यों नहीं है? क्या कारण है कि इतने बड़े छल से हमारे वास्तविक इतिहास को हमसे छिपाया गया? आज भारत के इतिहास का जिक्र होते ही रामसेतु का नहीं बल्कि ताजमहल का वर्णन गाया जाता है, कोणार्क का नहीं बल्कि कुतुबमीनार और आक्रान्ताओं के मकबरों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। यहीं हम अगर रामसेतु की बात करें तो वह समुद्र पर बनाया मानव निर्मित पुल बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बना था। हम सभी जानते हैं कि यह भारत के वास्तविक इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन इसका जिक्र हमारी पुस्तकों में दूर- दूर तक पढ़ने को नहीं मिलता है। भारत को सोने की चिड़िया कहने का सबसे बड़ा कारण भारत की संस्कृति रही है न कि मुगलों की शान कही जाने वाली ये व्यर्थ की इमारते और हीरे जवाहरात। भारत का वास्तविक इतिहास यहां कि संस्कृति है न कि मुगलों द्वारा बनवाए गए मकबरे। भारतीय संस्कृति की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही कार्यों को सम्पन्न किया जाता था। इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक जड़ी-बुटियों में मरीज को सही करने की वह ताकत थी जो किसी अन्य देश की अंग्रेजी दवाईयों में नहीं थी। भारत की संस्कृति कितनी सम्मान योग्य है, इसका सबसे सुंदर उदाहरण थाईलैण्ड, इंडोनेशिया में देखा जा सकता है। शोध के अनुसार थाइलैण्ड का राष्ट्रीय ग्रन्थ रामायण माना जाता है। इंडोनेशिया में महाभारत और भागवत गीता की लोकप्रियता इतनी है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कृष्णोपेडासाम नाम से कृष्ण की एक मूर्ति है, जहां अर्जुन और कृष्ण एक रथ पर सवार हैं। इसके द्वारा भगवतगीत के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। यहां रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है।

सनातन संस्कृति की शिल्पकला और वास्तुकला के आगे अच्छी-अच्छी संस्कृति नतमस्तक हो जाती हैं। भारतीय संस्कृति में निहित मन्दिर आन्ध्र प्रदेश का सूर्य नारायण, राम मन्दिर, रामसेतु, गुजरात का सूर्य मन्दिर, कर्नाटक का श्रीकान्तेश्वर, अमृतेश्वर, चिकमंगलूर, भोग नंदेश्वर, चेन्नकेशव, अनेगुड्डे, महाराष्ट्र का श्रीलक्ष्मी नृसिंह, द्वारिका का द्वारिकाधीश, मध्यप्रदेश का मां मक्रवाहिनी, तमिलनाडू का नैलायप्पार, बृहदीश्वर इन सभी मन्दिरों का इतिहास किसी भी पुस्तक में नहीं दिया गया है। पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित आक्रान्तियों द्वारा किए गए छल-कपट का एक बहुत बड़ा आईना है। मुगलकाल में इस मन्दिर के ऊपरी हिस्से को मस्जिदनुमा आकार दिया गया था, जिससे कि इसे मस्जिद समझकर तोड़ा न जाए और इस बात से आज भी समाज भलीभांति परिचित है। उस मन्दिर को मस्जिद का रूप देने के दौरान अनेंकों बार आक्रमण किया गया किन्तु यह हमारे आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है कि आज भी वह मन्दिर सुरक्षित है। इतना ही नहीं मन्दिर के भीतर प्राचीन शिवलिंग के साथ रामायण से जुड़े हुए कई तथ्य मूर्तियों के रूप में विघमान हैं।

मेरे विचार में भारतीय संस्कृति के ज्ञान हेतु स्कूली शिक्षा में रामायण और महाभारत से जुड़े हुए विषय पढ़ाए जाने चाहिए, साथ ही रसायन युक्त दवाईयों से ज्यादा योग, प्राणायम का अध्ययन कराया जाना चाहिए। जिससे आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को जाने। यहां की होम्योपैथी दवाएं हो या वेद-पुराण में निहित मंत्र, यह सम्पूर्ण मानव जाति को लाभ देने वाला यह हमारी संस्कृति बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी भी राष्ट्र के पतन अथवा उसके खण्डन के लिए सबसे पहले उसकी जड़ें अर्थात् उसकी संस्कृति को खत्म किया जाता है, यही भारत की संस्कृति के साथ हुआ है। अत यदि हमें अपने राष्ट्र, उसकी संस्कृति और उसके वास्तविक इतिहास को बनाए रखना है तो सबसे पहले हमें उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और यह ज्ञान आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसी ज्ञान को अपने स्वंय के जीवन में उतारकर ही हम अपने राष्ट्र को सोने की चिड़िया का रूप देते हुए उसका रक्षण कर पाएंगे। पहले से अधिक गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं।

आस्था के साथ खिलवाड़: शिकायत पर प्रशासन खामोश

अनुज शुक्ला

सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद प्रदेश के भीतर हिन्दू आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों में अपने धर्म और आध्यात्मिक विकास की एक उम्मीद जगी थी लेकिन तेजी से बढ़ती जा रही प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही ने कहीं न कहीं उनके भरोसे को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश के एक जिले में अति प्राचीनतम मंदिर के विकास हेतु जहां वर्षों से भक्त से लेकर पुजारी तक संघर्ष कर रहे हैं, वहीं मामले से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी भक्तों की आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हट रहे।

केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद सबसे अधिक और सबसे विशेष प्रभाव यदि किसी धर्म या किसी संस्कृति पर पड़ा है तो वह हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर देखने को मिला क्योंकि सरकार बनने के बाद खासकर मोदी और योगी सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए उनकी सुरक्षा और उनके सकारात्मक विकास का कार्य भी तेजी से किया जाने लगा। ऐसा हो भी क्यों न? सरकार बनाने में पूरे समाज के साथ सबसे बड़ा योगदान हिंदुओं का रहा। लेकिन, उत्तर प्रदेश के एक जिले में ऐसा मामला देखने को मिला, जिसने हिंदुओं के विश्वास के रूप में देखी जाने वाली सूबे की भाजपा सरकार पर एक नया प्रश्नचिन्ह लगा कर रख दिया।

मामला प्रदेश की राजधानी से महज 90 किमी. की दूरी पर स्थित सीतापुर जिले के जनपद मुख्यालय से लगभग 15 किमी. दूर परसेडी ब्लॉक के उलजापुर ग्राम पंचायत में अति प्राचीन कहे जाने वाले माता काली के मंदिर का है, जिसकी स्थापना आजादी के पूर्व की बताई जा रही है।

मंदिर की स्थापना 'मौनी बाबा' के नाम से विख्यात पंडित श्री राम मिश्र जी के द्वारा करायी गयी थी। मंदिर के प्रांगड़ में रोजाना होने वाले चमत्कारों की कहानी देश के कोने-कोने में हवा की भांति फैली हुई है। जिसके चलते दूर-दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, हिन्दू धर्म के सबसे पवित्र पर्व के रूप में माना जाने वाला नवरात्रि का पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है और इसी दिन खास तौर पर यहां दोनों नवरात्रियों पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ का दर्शन के उद्देश्य से रोजाना आना-जाना लगा रहता है। मान्यता यह भी है कि मंदिर के प्रांगड़ में माता रानी की भव्य प्रतिमा के पास कई भक्त आस्था के चलते अपनी जुबान भी काट कर माता के चरणों में अर्पित कर चुके हैं, जिसके बाद उनके द्वारा मांगी गई इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि इतनी मान्यताएं होने के बाद भी उस मंदिर का विकास आज भी अधूरा ही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित ऐसे मंदिर भारत के प्राचीन धरोहर की श्रृंखला में गिने जाते हैं। सरकार बनने के इतने वर्षों बाद भी इस मंदिर का विकास न होना कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ और लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। मंदिर में मौजूद भक्तों और अन्य लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि भाजपा सरकार को बने हुए केंद्र में 6 वर्ष और राज्य में 3 वर्ष लगभग हो चुके हैं लेकिन भक्तों की

आस्था से जुड़ी हुई इस पीड़ा को सुनने वाला इस सरकार में कोई अधिकारी नहीं है। बताया जाता है कि मन्दिर के पण्डित व संस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित श्रीराम मिश्रा की मृत्यु वर्ष 2009 के मई माह में हो गई थी। मंदिर के विकास के लिए उनके द्वारा भी अनेकों प्रयास किए गए लेकिन मंदिर तो दूर की बात है, यहां तो मंदिर तक भक्तों को ले जाने वाली सड़क भी बन पाई है और न ही मंदिर को रोशन करने वाली बिजली के तार मन्दिर तक पहुंच पाए। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि ब्लॉक के अधिकारीगण मामले से जुड़ी हुई कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

मंदिर के वर्तमान पुजारी प्रताप नारायण शुक्ल ने बताया कि वे पिछले 5 वर्षों से मंदिर के विकास हेतु निरन्तर संघर्ष कर रहे हैं। मामले से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी इस कार्य में भक्तों का सहयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहा। अधिक समय व्यर्थ बीतता हुआ देख पुजारी द्वारा वर्ष 2017 में सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत संख्या-40015418006012

दिनांक 05/02/2018 में दर्ज कराई गई लेकिन उस शिकायत से भी कोई लाभ नहीं हुआ और शासन से जुड़े हुए मामले का हवाला देकर भक्तों की आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाने लगा। मन्दिर के पुजारी का कहना है कि प्रशासन द्वारा मामले से जुड़ी हुई दी गई आख्या में लिखा गया है कि उक्त शिकायत की जाँच इफ्तिखार अली ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की गई, उनकी आख्यानुसार उक्त कार्य चौदहवें वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त मनरेगा की कार्य योजना में न होने के कारण इसको अभी कराया नहीं जा सकता, कुछ समय बाद जब आगे कार्य योजना बनाई जाएगी तो इस रोड का नाम कार्ययोजना में डाल कर स्वीकृत कराकर पूर्ण करा दिया जाएगा। इस प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह हैं कि मामले को लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक न तो कोई कार्य योजना बनी और न ही रोड का निर्माण हुआ। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि ब्लाक परसेडी के खंड विकास अधिकारी से लेकर गाँव के प्रधान तक सभी कुंभकरणी नींद में सो रहे हैं। इसी दौरान कई प्रतिष्ठित अखबारों के माध्यम से भी इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों और मन्दिर के पुजारी द्वारा लगातार आवाज उठाई जाती रही है लेकिन प्रशासन की अभी तक आंख नही खुल सकी। कुछ समय पहले भी पुजारी प्रताप नरायण शुक्ल द्वारा एक और शिकायत की गई तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार पाल द्वारा जांच कराई गई और आश्वासन दिया गया कि इस रोड का स्टीमेट बनवा कर शीघ्र ही निर्माण कार्य करा दिया जाएगा लेकिन शिकायत के लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की जा सकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब कार्य योजना नहीं बन पाई तो आखिर रोड का निर्माण होगा भी या नहीं?

मंदिर के पुजारी प्रताप नरायण शुक्ल का कहना है कि शिकायतें हमने भी बहुत की लेकिन जिले से लेकर ब्लॉक तक कोई सुनने वाला नहीं है। अनेकों अखबरों में खबरें भी प्रकाशित हुई लेकिन यहां पर न तो कोई अधिकारी जांच करने आया और न ही रोड का निर्माण हुआ। आने-जाने में भक्तों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर रोड का निर्माण भी हो जाता है तो मंदिर में आवागमन करने वाले अनेकों भक्तों को

कोई समस्या भी नहीं होगी और मंदिर विकास का एक कार्य भी पूर्ण हो जाएगा।

कुछ दिन पहले ही हुआ था गांव में बिजली कनेक्शन का कार्य: ग्रामवासी बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही गांव में बिजली विभाग द्वारा कार्य कराया गया था। उस वक्त भी गांव वालों ने अधिकारियों से मंदिर में बिजली कनेक्शन न होने की बात कही थी, जिसपर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान न देकर सिर्फ आश्वासन दिया गया और अपना काम करके चलते बने। भक्तों का कहना है कि जिम्मेदारों द्वारा लगातार उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे उनकी आस्था को चोट पहुंच रही है।

लोगों की आस्था से खिलवाड़ पड़ सकता है महंगा: ग्रामवासियों और मन्दिर में आने वाले भक्तगणों ने बताया कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन कुम्भकर्णी नींद में सोया हुआ है, जिससे साफ जाहिर है कि जिम्मेदार सिर्फ हमारी आस्था का मजाक बना रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग एक साथ मुख्यमंत्री जी से शिकायत करने जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों की शिकायत करेंगे।

जिम्मेदार अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान: इस मामले को लेकर जब स्वतंत्र स्वरूप के जिला संवाददाता ने ग्राम विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है जबकि शिकायत की जांच और उसकी आख्या इन्ही के द्वारा लगाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार सिर्फ कागजों पर ही खानापूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अधिकारी बिना किसी जांच और मौका मुआयना किये ही सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं और नागरिकों को सिर्फ आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।

क्या बोले एडीओ पंचायत परसेडी: इस मामले को लेकर जब एडीओ पंचायत से बात की गई तो उन्होंने भी इस बारे में कोई जानकारी न होना बताया। उन्होंने कहा कि जानकारी तो नहीं है लेकिन इतना बता सकते हैं कि कौन से कार्य होने हैं और इसकी प्राथमिकता ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम प्रधान ही तय करते हैं। ऐसे में जो कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तय किये जाते हैं, उन्हें ही स्वीकृति मिलती है। इसके लिए हम कोई कार्य योजना नहीं बनाते हैं। अगर ग्राम प्रधान चाहे तो जिम्मेदारों को बुलाकर एक प्रस्ताव पास करवा सकता है और कार्य भी करा सकते हैं, बशर्ते वे कार्य कराने के इच्छुक हो।

आवारा पशु हैं इनके दोस्त, मिलिए 'सच्चे इंसान' से

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

ये प्रकृति, ये जीव-जंतु जिनका शायद आज के समय में हमारे जीवन में कोई मूल्य ना हो फिर भी वह सभी बिना स्वार्थ के हमारे प्रति समर्पित ही रहते हैं। हम पेड़ों को काटते हैं, फिर भी अन्य पेड़ हमें छाया देना बंद नहीं करते, हम दुधारू पशुओं के प्रयोग ना आने पर मारते हैं, पीटते हैं इतना ही नहीं कसाईखाने भी भेज देते हैं, क्या इसका विरोध करने के लिए वह हमें दूध या उपयोगी वस्तुएँ उपलब्ध कराना बंद कर देते हैं?

हम सभी इस बात से परिचित हैं कि इस धारती रहने वाले हर जीव के जीवन का आधार प्रेम है और वह सिर्फ मानवजाति के लिए ही नही बल्कि पशु, पक्षी, जीव-जंतु सभी के लिए है। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना होगा कि हम सारे समाज से प्रेम करते हैं, सारे समाज को अपनाते हैं। लेकिन क्या उन लोगों को ये पता है कि समाज क्या है, किस समाज को अपनाने की हम बात करते हैं उस समाज में कौन-कौन आता है ? शायद नहीं! क्योंकि हमने समाज में सिर्फ उन लोगों को देखा है, उन लोगों को ही अपनाया है जिनसे हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा होता है।

हम उन्ही के विषय में सोचते हैं उन्हीं के लिए कार्य करते हैं, जो हमारे लिए समर्पित रहते हैं। हकीकत तो यह है कि हम जानते ही नहीं कि आज के समय में प्रेम की आवश्यकता किसे है? और शायद हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। क्या कभी विचार किया है कि वर्तमान समय में प्रेम और समर्पण के नाम पर चला रहे लेन-देन के कारोबार में भी हम बेईमानी करते हैं ?

ये प्रकृति, ये जीव-जंतु जिनका शायद आज के समय में हमारे जीवन में कोई मूल्य ना हो फिर भी वह सभी बिना स्वार्थ के हमारे प्रति समर्पित ही रहते हैं। हम पेड़ों को काटते हैं, फिर भी अन्य पेड़ हमें छाया देना बंद नहीं करते, हम दुधारू पशुओं के प्रयोग ना आने पर मारते हैं, पीटते हैं इतना ही नही कसाईखाने भी भेज देते हैं, क्या इसका विरोध करने के लिए वह हमें दूध या उपयोगी वस्तुएँ उपलब्ध कराना बंद कर देते हैं? नहीं...बल्कि जीवन की भागदौड़ में हम कितना भी उन्हें भूल जाएं लेकिन वे हमें नही भूलते।

हम अक्सर कहानी, किस्सों में पढ़ते होंगे की इंसान से ज्यादा कादार जानवर होते हैं, हो भी क्यों ना .....मालिक के हाथ की एक रोटी के बदले पूरे दिन की पीड़ा तक भूल जाते हैं। इतना सब सहने के बाद भी हम उन्हें प्रेम नहीं दे पाते। जबकि वास्तविक प्रेम के हकदार ये जीव हैं, ये पशु-पक्षी हैं। जरा सा प्रेम पाकर वे अनजान से मनुष्य के एक सच्चे मित्र का सफर तय कर लेते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है लखनऊ का। जहाँ अजय श्रीवास्तव नाम के युवक और आवारा पशुओं की सच्ची मित्रता एक मिसाल कायम कर रही है।

अजय मूलत: लखनऊ के निवासी हैं, साथ ही मार्शल आर्ट्स की एक विधा 'वुशू' के खिलाड़ी हैं। पूर्व में वह वुशू खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। ऐसे ही कई बड़े सम्मानों के बाद भी वे संघर्ष कर अपने जूनियर्स के लिए एक प्रेरणास्त्रोत का काम कर रहे हैं। अपने घर पर पले हुए जानवरों को दिन की दो रोटी देकर हर कोई उसे सेवा का नाम दे देता है।

लेकिन यहाँ अजय की कहानी कुछ अलग ही है, वह घर की दहलीज पर पले जानवरों का नहीं बल्कि उन जानवरों के लिए प्रतिदिन भोजन से लेकर रहने तक का प्रबंध करते हैं जिन्हें अक्सर हम आवारा या लावारिस कहकर दुत्कार देते हैं। अजय के मुताबिक उन जानवरों में सड़क पर घूमने वाली गाय के साथ आवारा कुत्तों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं और यह कार्य उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल हैं। अजय एक हरिवंश राय बच्चन ग्रामीण स्मृति सेवा संस्थान समिति नामक संस्था के लिए कार्य करते हैं यह संस्था जनकल्याण के लिए समर्पित होकर समय समय पर लोकहित के लिए अनेकों योजनाओं के तरह काम करती हैं। अजय ने बताया कि वे यह कार्य लगभग 12 वर्षो से नि:स्वार्थ भाव से करते आ रहे हैं।

कैमरे की नजर में...

हेमेन्द्र त्रिपाठी
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अजय कुमार
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

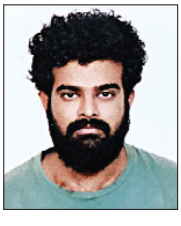

अमित दुबे
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सर्वेश शुक्ला, अधिशासी अधिकारी
एवं समस्त सदस्यगण नगर पंचायत सिधौली जनपद सीतापुर

समस्त अभिवावको छात्र-छात्राओं एवं नगरवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

संजय जैन

प्रबन्धक श्री विमलनाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय
सिधौली, सीतापुर

समस्त क्षेत्रवासियों व जनपद वासियों को स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक बधाई

अरविन्द कुमार सचिव
ग्राम सभा- कुकुरा, ऐरा, काकेमऊ इटौंजा/क्षेत्र पंचायत-भरावन
तहसील- सण्डीला, जनपद हरदोई

सुन्दरलाल सचिव
ग्राम पंचायत- सोनिकपुर, बकवा, कोइली
क्षेत्र पंचायत-भरावन जनपद हरदोई

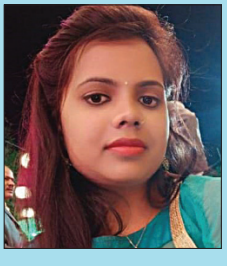

स्वाती सिंह सचिव
ग्राम पंचायत- दुलानगर, हीरूपुर गोटैया
क्षेत्र पंचायत- भरावन हरदोई

PHYSIO INTERNATIONAL
AN ADVANCED THERAPY SYSTEM
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
Manufacturer & Suppliers of
Physiotherapy
Rehabilitation
Slimming
Beauty
Surgical Equipments
+91 70112 31225 / 92666 99951
physioint@gmail.com
www.physiointernational.in

Sale 30 % Off
Residencial Plots ,Ready To Move Flats
LDA Approved
Easy loan option
Call @ 7275379043

INCOME TAX RETURN
SPECIAL OFFER
FILE NOW
STARTING- 499 ONLY/-
CAREMYTAX
LIMITED TIME ONLY
SPECIAL OFFER
ITR
Income Tax Return
SPECIAL PRICE FOR ALL
call or whatsapp @ 9838111122
https://caremytax.com

पत्रकार बनना है?
हमें डिग्री नहीं, जुनून चाहिए
समाज की हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर
बनिए हमारी टीम का हिस्सा
भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए
ब्लू बर्ड्स मीडिया ग्रुप से जुड़ें
स्वतंत्र स्वरूप
EDUCATION BEATS
THE REPUBLIC TIMES
इंडिया MIRROR
Nation. First.
दैनिक समाचार पत्र
राष्ट्रीय मासिक पत्रिका
शिक्षा आधारित न्यूज पोर्टल
नेशनल न्यूज पोर्टल
यूट्यूब चैनल
88404 73248
88879 73576
jobs.bbmedia@gmail.com
दलाली के लिए प्रेस का कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कतई संपर्क न करें